

कमल संदेश



‘आतंकवाद न तो लेफ्ट होता है न ही राइट, केवल आतंकवाद होता है’

वर्ष-14, अंक-15

01-15 अगस्त, 2019 (पाक्षिक)

₹20

चंद्रयान-2

‘हृदय से भारतीय,
भाव से भारतीय’





रांची (झारखंड) में बुद्धिजीवियों को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा



झारखंड में भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के बाद रांची में वृक्षारोपण करते भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा



गांधीनगर (गुजरात) में भाजपा कोर ग्रुप, पदाधिकारियों, मोर्चा और जिलाध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा



गुजरात स्थित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर लौहपुरुष सरदार बल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा



दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर 'विजय ज्योति' को भारतीय सेना को सौंपते केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह



केवल एथनॉल ईंधन से चलने वाली बाइक का शुभारंभ करने के बाद जनसमूह को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी

संपादक

प्रभात झा

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

राम नयन सिंह

कला संपादक

विकास सैनी

मुकेश कुमार

संपर्क

फोन: +91(11) 23381428

फैक्स

फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल

mail.kamalsandesh@gmail.com

mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org



भारत ने किया 'चंद्र मिशन-2' का सफल प्रक्षेपण



भारत ने "अनगिनत सपनों को चांद पर ले जाने" के उद्देश्य से अपने दूसरे चंद्र मिशन 'चंद्रयान-2' का 22 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। 'बाहुबली' नाम के सबसे ताकतवर रॉकेट जीएसएलवी-मार्क 43.43 मीटर लंबे...

वैचारिकी

राजनीतिक विकेंद्रीकरण का ही दूसरा नाम प्रजातंत्र है 17

श्रद्धांजलि

नहीं रहे मांगेराम गर्ग 19

लेख

राज्यसभा: कामकाज के लिहाज से उपयोगी सत्र 28

पड़ोसी देशों से संबंध सुधार के प्रयास 30

अन्य

कुलभूषण जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर फिर से... 16

आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिये कठोर कानून जरूरी... 20

आतंकवाद न तो लेफ्ट होता है न ही राइट, केवल आतंकवाद... 21

मोदी सरकार 2.0 के प्रथम 50 दिन 22

पार्टी को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने के लिए मेहनत करें... 24

भाजपा के पास नेता भी हैं, नीति भी है और नीयत भी 26

'आप और हम मिलकर अपना सर्वोच्च हासिल करेंगे' 27

लोकसभा की उत्पादकता 20 साल में सबसे ज्यादा 31

मंत्रिमंडल ने 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार... 32

संसद ने आरटीआई संशोधन विधेयक को दी मंजूरी 33



11 भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) नियुक्त हुए बीएल संतोष

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 14 जुलाई, 2019 को पार्टी के राष्ट्रीय सह...

13 राधामोहन सिंह भाजपा के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 19 जुलाई को संगठनात्मक चुनाव के संचालन के लिए सांसद एवं पूर्व केंद्रीय कृषि...



14 अदालतों में 61 प्रतिशत कम हुई अप्रत्यक्ष कर मामलों की संख्या

देश की अदालतों में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित लंबित अपील की संख्या करीब दो साल में 61 प्रतिशत घटकर 1.05 लाख रह...



15 नरेन्द्र मोदी भारत में 2019 के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति हैं और विश्व में पसंदीदा पुरुषों...



twitter

@narendramodi



आज समय की मांग है कि मानवता में विश्वास रखने वाली सभी शक्तियां सशस्त्र बलों के साथ उनके समर्थन में खड़ी हों, तभी आतंकवाद का प्रभावी तौर पर मुकाबला किया जा सकता है।

@AmitShah



मोदी सरकार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक 2019 का कभी दुरुपयोग नहीं होने देगी। इस कानून का शुद्ध रूप से उपयोग देश से आतंकवाद को खत्म करने के लिए ही किया जाएगा। और आतंकवाद को खत्म करते वक्त हम यह भी नहीं देखेंगे कि यह किस धर्म के व्यक्ति ने किया है।

@JPNadda



भाजपा आज बड़े वटवृक्ष के रूप में खड़े होकर करोड़ों लोगों को छाया एवं दिशा दे रही है। इसके लिए लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन लगाया है। आप भाजपा में चाहे अपनी इच्छा से आए हों, संयोग से आए हों या किसी अन्य कारण से, पर आप भाग्यशाली हैं कि आप देश की सर्वश्रेष्ठ पार्टी में आए हैं।

facebook

जब भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान सारी दुनिया करती है तो गांव-गांव तक के नागरिकों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। देश की जनता का अद्भुत समर्थन प्रधानमंत्री जी को प्राप्त है। पं. दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का संदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक गरीब नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्यरत हैं। भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च आना अभी बाकी है। हमें संगठन का विस्तार करना है जिसका आधार है सदस्यता इसलिए देश के नवनिर्माण में भागीदार बनें, पार्टी का हिस्सा बनें।
— शिवराज सिंह चौहान



हमारी सरकार ने हिमाचल में निवेश को व्यापक बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ महीनों में 27,515 करोड़ के निवेश की 228 परियोजनाओं के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में निवेशक राज्य में निवेश करने के लिए आगे आए हैं। हमारा ध्येय प्रदेश को विकास की राह पर शिखर तक पहुंचाना है।



— जयराम टाकुर

समूचा भारत हमारी निष्ठाओं का केन्द्र और हमारा कार्यक्षेत्र है। भारत की जनता हमारा आराध्य है। हमें अपनी स्वाधीनता को अमर बनाना है, राष्ट्रीय अखंडता को अक्षुण्ण रखना है और विश्व में स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीवित रहना है। इसके लिए हमें भारत को सुदृढ़ शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बनाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो साधन आवश्यक होगा, हम अपनाएंगे; जो नीति उपयोगी होगी, उसका अवलम्बन लेंगे, जो कार्यक्रम हितावह होगा, उसका निर्धारण तथा कार्यान्वयन करेंगे।

कंधे से कंधा लगाकर, कदम से कदम मिलाकर हमें अपनी जययात्रा को ध्येय-सिद्धि के शिखर तक ले जाना है। भावी भारत हमारे प्रयत्नों और परिश्रम पर निर्भर करता है। हम अपना कर्तव्य पालन करें, हमारी सफलता सुनिश्चित है।

— अटल बिहारी वाजपेयी



कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

आकांक्षाओं से उपलब्धियों तक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की करिश्माई एवं दूरदर्शी नेतृत्व में भारत को सफलता पर सफलता प्राप्त हो रही है। इतना ही नहीं, इन सफलताओं को पूरा विश्व स्वीकार कर अद्भुत उपलब्धियों के रूप में विस्मय भरी नजरों से देख रहा है। आने वाले वर्षों में भी देश यदि इसी तरह से उड़ान भरता रहा तब वह दिन दूर नहीं कि मां भारती विश्व गुरु के अपने आसन पर पुनः आसीन होंगी। यह कुछ ही वर्षों पहले की बात है जब कांग्रेसनीत यूपीए के शासन में देश भ्रष्टाचार, कुशासन, 'नीतिगत पंगुता' से जूझ रहा था और चारों ओर निराशा से भरा एक नकारात्मक वातावरण था। पिछले पांच वर्षों की कड़ी मेहनत, अथक प्रयास, अभिनव योजनाएं, भ्रष्टाचारमुक्त सरकार और भारत को एक महान् राष्ट्र बनाने के संकल्प से न केवल देश की स्थिति सुधारी गई बल्कि गौरवशाली भविष्य का मार्ग प्रशस्त हुआ है। देश की इस यात्रा को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सक्षम नेतृत्व प्राप्त है जिससे प्रेरणा लेकर जन-जन के मन में एक नए क्षितिज को छूने के बीज अंकुरित हुए हैं।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम 50 दिन में उठाये गए कदमों से देश में आशा एवं विश्वास का एक नया वातावरण का सूत्रपात हुआ है। जिस प्रकार से संसद के दोनों सदनों ने वर्तमान सत्र में कार्य किया है तथा हाल के वर्षों में अब तक का सर्वाधिक सफल सत्र साबित हुआ है, उससे देश की जनता में एक नया विश्वास जगा है तथा संसदीय लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा और अधिक सुदृढ़ हुआ है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों एवं विषयों पर चर्चा हुई है। मोदी सरकार ने जहां किसानों को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है वहीं 2022 तक उनके आय को दुगुना करने के लक्ष्य प्राप्ति के क्रम में अनेक किसान समर्थक नीतियां बना रही है। खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़त कर तथा 'प्रधानमंत्री-किसान योजना' की परिधि में देश के हर किसान को लाकर सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। इसी तरह श्रमिक कानून में सुधार कर न केवल 49 करोड़ श्रमिकों के कल्याण का कार्य किया बल्कि अर्थव्यवस्था में गतिरोधों को दूर कर 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' के सिद्धांतों को मजबूत किया है। मोदी सरकार 2022 तक 1.95 करोड़ पक्के घरों के निर्माण को प्रतिबद्ध है साथ ही हर घर में गैस और बिजली कनेक्शन पहुंचाने के संकल्प के साथ तेज गति से कार्य कर रही है। वास्तव में देखें तो ग्रामीण क्षेत्र तथा किसानों पर ध्यान देकर मोदी सरकार ने अब तक उपेक्षित भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ को बहुत ही मजबूत कर दिया है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से न केवल करोड़ों परिवारों को राहत मिली है बल्कि 'अंत्योदय' की अवधारणा के अनुरूप गरीब से गरीब व्यक्ति का सशक्तिकरण भी हुआ है।

अनेक प्रकार की अभिनव योजनाओं के कार्यान्वयन में जिस प्रकार से 'स्पीड, स्केल एवं स्किल' दिखा है उससे समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति तक इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव अत्यधिक मजबूत हुई है। यही कारण है कि आज भारत 2024

तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के आत्मविश्वास से भरा हुआ है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की शक्ति ही है जिससे अब तक दुष्कर से लगने वाले लक्ष्य भी सुगम बनते जा रहे हैं। चन्द्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण से एक आत्मविश्वास से ओत-प्रोत भारत के उदय को पूरा विश्व ने देखा है। आज जब भारत की नीतियों का समर्थन पूरे विश्व में हो रहा है, मोदी सरकार लगभग हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। जम्मू-कश्मीर एवं एनआईए पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गृहमंत्री श्री अमित शाह के संबोधन से यह प्रमाणित हो गया है कि भारत दृढ़ निश्चयी होकर कुशलता से आगे बढ़ रहा है। भारत के इस उदय का महत्व तब समझा जा सकता है जब श्री नरेन्द्र मोदी को पूरे देश के द्वारा एकजुट मिले दो जनादेशों के संदर्भ में देखा जाय। आज हर क्षेत्र में भारत सफलता के झंडे गाड़ रहा है तथा संपूर्ण राष्ट्र की यात्रा आकांक्षाओं से लेकर उपलब्धियों तक हो रही है। ■

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम 50 दिन में उठाये गए कदमों से देश में आशा एवं विश्वास का एक नया वातावरण का सूत्रपात हुआ है। जिस प्रकार से संसद के दोनों सदनों ने वर्तमान सत्र में कार्य किया है तथा हाल के वर्षों में अब तक का सर्वाधिक सफल सत्र साबित हुआ है, उससे देश की जनता में एक नया विश्वास जगा है।



भारत ने किया 'चंद्र मिशन-2' का

रूस, अमेरिका, चीन के बाद चांद्र पर उतरने वाला



भारत ने “अनगिनत सपनों को चांद पर ले जाने” के उद्देश्य से अपने दूसरे चंद्र मिशन ‘चंद्रयान-2’ का 22 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ‘बाहुबली’ नाम के सबसे ताकतवर रॉकेट जीएसएलवी-मार्क 43.43 मीटर लंबे जीएसएलवी मार्क III एम-1 ने प्रक्षेपण के करीब 16 मिनट बाद यान को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया।

चंद्रयान-2 ने अपराह्न दो बजकर 43 मिनट पर चांद की ओर उड़ान भरी। यह प्रक्षेपण अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की धाक जमाएगा और चांद के बारे में दुनिया को नई जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसरो ने 18 जुलाई को यान के प्रक्षेपण की नयी तारीख की घोषणा करते हुए कहा था “चंद्रयान-2 अनगिनत सपनों को चांद पर ले जाने के लिए तैयार है। 22 जुलाई 2019 को अपराह्न दो बजकर 43 मिनट पर प्रक्षेपण के लिए हमारे साथ जुड़िये।”

43.43 मीटर लंबे जीएसएलवी मार्क III एम-1 ने आसमान में छाए बादलों को चीरते हुए प्रक्षेपण के करीब 16 मिनट बाद 3,850 किलोग्राम वजनी ‘चंद्रयान-2’ को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। प्रक्षेपण के बाद इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने के साथ ही यान ने भारत के महत्वाकांक्षी मिशन के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया।

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने चंद्रयान-2 की सफल लॉन्चिंग पर इसरो के सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, “श्रीहरिकोटा से चन्द्रयान-2 का ऐतिहासिक प्रक्षेपण हर भारतीय के लिए एक गर्व का क्षण है। भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए @ISRO के सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। मेरी कामना है कि टेक्नालॉजी के नए-नए क्षेत्रों में ‘इसरो’ नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचे।”

उपराष्ट्रपति श्री एम. वैकेया नायडू ने चन्द्रयान-2 के सफल लॉन्च के लिये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और अंतरिक्ष विभाग के वैज्ञानिकों और कर्मियों को बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने इस बात की बहुत सराहना की कि चन्द्रयान-2 और प्रक्षेपण वाहन पूरी तरह भारत में ही निर्मित है।

उन्होंने कहा, “यह निश्चित रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति का सुनहरा अध्याय और मील का पत्थर है।” उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि चन्द्रमा की उस सतह पर उतर कर चन्द्रयान-2 परियोजना



सफल प्रक्षेपण

चाँदा चौथा देश होगा भारत

चन्द्रयान पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है : नरेन्द्र मोदी

हृदय से भारतीय, भाव से भारतीय!

देश के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि विशेष पल जो हमारे गौरवशाली इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। चंद्रयान-2 के लांच से विज्ञान में नई ऊंचाइयां छूने के लिए हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता और 130 करोड़ भारतीयों की प्रतिबद्धता प्रकट होती है। आज हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है।

उन्होंने कहा कि हृदय से भारतीय, भावना से भारतीय! हर भारतीय के लिये प्रसन्नता का विषय है कि चंद्रयान-2 पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है। चंद्रमा के धरातल का विश्लेषण करने के लिए चंद्रयान-2 में चंद्रमा के संबंध में दूर संवेदन के लिए एक आर्बिटर तथा लैंडर- रोवर मॉड्यूल होगा।

श्री मोदी ने कहा कि चंद्रयान-2 इसलिए विशिष्ट है, क्योंकि यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन और जांच करेगा, जहां अभी तक कोई खोज नहीं हुई थी। इस क्षेत्र से पहले नमूने भी कभी नहीं लिये गए। इस मिशन से चंद्रमा के बारे में नई जानकारियां मिलेंगी।

उन्होंने कहा कि चंद्रयान-2 जैसे प्रयासों से हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान, उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान और नवाचार के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा। चंद्रयान को धन्यवाद, भारत के चंद्र कार्यक्रम को बहुत बढ़ावा मिलेगा। चंद्रमा के बारे में हमारे मौजूदा ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी।”

सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी, जहां अब तक कोई भी मानव निर्मित वस्तु नहीं पहुंच सकी है।

श्री नायडू ने कहा, “यह पहल बाहरी अंतरिक्ष की खोज में भारत के योगदान के मद्देनजर एक बड़ी छलांग है तथा भारत उन तीन देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने इसी तरह के चुनौतीपूर्ण अभियानों का आयोजन किया है। यह निश्चित रूप से पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देश की तेज प्रगति का जीवंत प्रमाण है।”

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए ट्वीट किया, “चंद्रयान-2 अपने आप में विशिष्ट है क्योंकि यह चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में खोज और अध्ययन करेगा जो किसी विगत मिशन में नहीं हुआ है। मिशन, चंद्रमा के बारे में नयी जानकारी उपलब्ध कराएगा।”

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कहा कि आर्बिटर, लैंडर और रोवर के साथ गया ‘चंद्रयान-2’ चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र

में उतरने से पहले 15 महत्वपूर्ण अभियान चरणों से गुजरेगा। यान के सितंबर के पहले सप्ताह में चांद पर उतरने की उम्मीद है।

प्रक्षेपण के बाद इसरो प्रमुख डॉ. के. सिवन ने मिशन के सफल होने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह चंद्रमा की ओर भारत की ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत है। डॉ. सिवन ने इस चुनौतीपूर्ण मिशन में शामिल रही प्रक्षेपण यान और उपग्रह टीमों को बधाई दी।

उन्होंने कहा, “भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए



आज एक ऐतिहासिक दिन है। मुझे यह घोषित करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जीएसएलवी एमकेIII-एम1 यान ने चंद्रयान-2 को 6,000 किलोमीटर की एक कक्षा तक सफलतापूर्वक पहुंचा दिया, जो वांछित कक्षा से अधिक एवं बेहतर है।”

डॉ. सिवन ने कहा, “आज चंद्रमा तक पहुंचने की भारत की ऐतिहासिक यात्रा तथा अब तक खोजे नहीं गये तथ्यों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग करने हेतु दक्षिणी ध्रुव के निकटवर्ती स्थान पर उतरने की शुरुआत है। 15 जुलाई, 2019 को इसरो ने बड़ी कुशलता के साथ एक तकनीकी गड़बड़ी का पता लगा लिया था। टीम इसरो ने 24 घंटे के भीतर ही इस गड़बड़ी पर काम करके, उसको ठीक कर सुधार दिया था। अगले डेढ़ दिन तक इस बात का पता लगाने के लिए आवश्यक परीक्षण किये गये कि सुधार उचित और सही दिशा में किये गये हैं अथवा नहीं। आज इसरो ने शानदार सफलता हासिल की।”

एक महान राष्ट्र को इस अतुलनीय उपलब्धि पर गर्व है: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने चंद्रयान-2 की सफल लॉन्चिंग को देश के लिए ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) एवं इस मिशन में कार्यरत सभी वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई दी।



श्री शाह ने कहा कि चंद्रयान-2 की सफल लॉन्चिंग के साथ ही हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष में एक और बड़ी छलांग लगाते हुए मिसाल कायम की है। एक महान राष्ट्र को इस अतुलनीय उपलब्धि पर गर्व है, क्योंकि हम चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव के हिस्से पर उतरने की कोशिश करेंगे जहां आज तक कोई भी देश पहुंच नहीं पाया है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भी धन्यवाद दिया और कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वे हमारे संस्थानों को इस तरह के शानदार काम करने के लिए सदैव प्रेरित करते रहते हैं।

श्री शाह ने कहा कि इसरो ने हाल के वर्षों में एक साथ 104 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित करने के साथ-साथ मंगलयान और चंद्रयान-1 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर पूरे विश्व को अचंभित कर दिया है। यह समस्त देशवासियों के लिए गौरवान्वित करने वाला है। चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग इस दिशा में एक और मील का पत्थर है।

इसरो का सबसे जटिल और अब तक का सबसे प्रतिष्ठित मिशन माने जाने वाले 'चंद्रयान-2' के साथ रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चांद्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। स्वदेशी तकनीक से निर्मित 'चंद्रयान-2' में कुल 13 पेलोड हैं। आठ ऑर्बिटर में, तीन पेलोड लैंडर 'विक्रम' और दो पेलोड रोवर 'प्रज्ञान' में हैं।

लैंडर 'विक्रम' का नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम ए साराभाई के नाम पर रखा गया है। दूसरी ओर, 27 किलोग्राम वजनी 'प्रज्ञान' का मतलब संस्कृत में 'बुद्धिमत्ता' है। ऑर्बिटर, चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेगा और पृथ्वी तथा 'चंद्रयान-2' के लैंडर 'विक्रम' के बीच संकेत प्रसारित करेगा। लैंडर 'विक्रम' को चंद्रमा की सतह पर भारत की पहली सफल लैंडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। 'प्रज्ञान' नाम का रोवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) संचालित 6-पहिया वाहन है।

डॉ. सिवन ने कहा कि यान को चंद्रमा के पास पहुंचने से पहले, अगले डेढ़ महीने में 15 "बेहद महत्वपूर्ण अभियान चरणों" से गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि उसके बाद वह दिन आएगा, जब चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव के नजदीक सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए 15 मिनट तक "हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी।" यह सबसे जटिल चरण होगा।

गौरतलब है कि गत 15 जुलाई को रॉकेट में तकनीकी खामी का



पता चलने के बाद 'चंद्रयान-2' का प्रक्षेपण टाल दिया गया था। उस दिन इसका प्रक्षेपण तड़के दो बजकर 51 मिनट पर होना था, लेकिन प्रक्षेपण से 56 मिनट 24 सेकंड पहले रॉकेट में तकनीकी खामी का पता चलने के बाद 'चंद्रयान-2' की उड़ान टाल दी गई थी। समय रहते खामी का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक समुदाय ने इसरो की सराहना की थी।

'चंद्रयान-2' चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरेगा जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है। इससे चांद्र के अनसुलझे रहस्य जानने में मदद मिलेगी। यह ऐसी नयी खोज होगी जिसका भारत और पूरी मानवता को लाभ मिलेगा।

पहले चंद्र मिशन की सफलता के 11 साल बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भू-स्थैतिक प्रक्षेपण यान जीएसएलवी-मार्क III के जरिए 978 करोड़ रुपये की लागत से बने 'चंद्रयान-2' का प्रक्षेपण किया।

चंद्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण के लिए संसद के दोनों सदनों ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी

संसद के दोनों सदनों ने 22 जुलाई को देश के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण पर संबंधित वैज्ञानिकों एवं परियोजना से जुड़े लोगों को बधाई दी और कहा कि यह पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है। इसके सफल प्रक्षेपण के कुछ देर बाद ही लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। यह देश के लिए गौरवशाली क्षण है।

उन्होंने कहा कि इस प्रक्षेपण के साथ ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की शक्ति और क्षमता को बढ़ावा मिला है। श्री बिरला ने कहा कि यह इसरो के वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संभव हुआ है। हम वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं। सदस्यों ने मेजें थपथपा कर इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की।

राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू ने भी उच्च सदन में इस उपलब्धि का जिक्र किया। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए देशवासियों, वैज्ञानिकों, इसरो के कर्मचारियों तथा अंतरिक्ष विभाग

130 करोड़ भारतीयों के लिए यह गर्व का विषय : जगत प्रकाश नड्डा

130 करोड़ भारतीयों के लिए यह गर्व का विषय है, कि पूर्णतया स्वदेशी #Chandrayaan2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर कर चंद्रमा की सतह का अध्ययन, विश्लेषण आदि शोध कार्य करेगा। जहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया आज वहां भारत की पहुंच है। इस अभियान से जुड़ी @isro टीम को हृदय से बधाई।



को बधाई दी। श्री नायडू ने कहा कि चंद्रयान-2 पूरी तरह से भारत में डिजाइन और तैयार किया गया है तथा इसलिए वैज्ञानिक विशेष प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी से देश का गौरव तथा विश्वास बढ़ा है। यह कामयाबी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा देश के लिए सुनहरा अध्याय होगी। ■

विदेशी मीडिया में भी हुई चंद्रयान-2 की 'प्रशंसा'

इसरो के चंद्रयान-2 मिशन की सभी देशों में प्रशंसा हुई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रयान-2 की सफल लॉन्चिंग के लिए इसरो को बधाई दी। अमेरिकी मीडिया ने भी भारत के इस मिशन को सराहा।

नासा ने इसरो को दी बधाई

चंद्रयान-2 की सफल लॉन्चिंग के लिए अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसरो को बधाई दी। नासा ने अपने एक ट्वीट में कहा, 'चंद्रयान 2 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए इसरो को बधाई। आपके इस मिशन में हम अपने डीप स्पेस नेटवर्क से सहयोग कर गर्व का अनुभव कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में जो आपको नई जानकारी प्राप्त होगी, उस जगह पर अगले कुछ वर्षों में हम अपने अर्टेमिस मिशन में अंतरिक्षयात्रियों को भेजेंगे।'

चंद्रयान-2 ने भारत के सम्मान को बढ़ाया :

वाशिंगटन पोस्ट

नासा के बधाई संदेश के बाद दुनिया की मीडिया में चंद्रयान-2 सुर्खियां बन गया। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि चंद्रयान-2 अपने मिशन पर ऐसे समय रवाना हुआ है जब चंद्रमा पर मनुष्य के कदम

रखने के 50 साल पूरे हुए हैं। अमेरिका का पहला मानवयुक्त मिशन अपोलो-II, 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरा था। अखबार ने कहा कि भारत ने 2022 तक अंतरिक्ष में मानवयुक्त मिशन भेजने की घोषणा की है। भारत की कम बजट वाली और स्वदेश निर्मित अंतरिक्ष तकनीक ने राष्ट्रीय सम्मान एवं आकांक्षाओं को बढ़ाया है।

न्यूयॉर्क टाइम्स ने की प्रशंसा

न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, 'लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान मिशन की शेष चीजें यदि व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ीं तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत 200,000 मील से ज्यादा दूर चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान-2 चंद्रमा के रहस्यमयी दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। चंद्रमा का यह हिस्सा अभी तक अछूता रहा है और दुनिया का कोई भी चंद्र मिशन अब तक इस क्षेत्र में नहीं पहुंचा है।'

अभिनंदन! अभिनंदन!

भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) नियुक्त हुए बीएल संतोष

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 14 जुलाई, 2019 को पार्टी के राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) श्री बी.एल. संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) नियुक्त किया। इससे एक दिन पूर्व लगभग 13 वर्षों तक राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) की जिम्मेदारी निभाने वाले श्री रामलाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में वापस चले गए और उन्हें संघ के 'अखिल भारतीय सह-सम्पर्क प्रमुख' का दायित्व सौंपा गया।

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल ने एक ट्वीट में कहा -

“श्री बी.एल. संतोष जी को भाजपा द्वारा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) के रूप में नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई। संतोषजी सक्षम, ऊर्जावान और मेहनती हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) के रूप में उनकी नियुक्ति से पार्टी को नई गति और ऊंचाई मिलेगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ”।

श्री बी.एल. संतोष दक्षिण कर्नाटक के चामाराजनगर से हैं, लेकिन उनका जन्म और पालन-पोषण बैंगलोर में हुआ। एक विनम्र पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले श्री संतोष अपनी योग्यता और कड़ी मेहनत के बल पर शीर्ष तक पहुंचे हैं।

श्री बी.एल. संतोष रा.स्व.संघ के 'प्रचारक' हैं। उनका राजनीतिक क्षेत्र में विशेष रूप से दक्षिण भारत का अनुभव अधिक है और उन्हें प्रमुख विचारकों में से एक माना जाता है। वे चुनाव प्रबंधन और पार्टी के संगठनात्मक दायित्वों को कुशलतापूर्वक निभाने के लिए



जाने जाते हैं।

2014 में भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) एवं दक्षिणी राज्यों के प्रभारी की जिम्मेदारी संभालने से पहले वे 2006 से आठ साल तक कर्नाटक में पार्टी के महामंत्री (संगठन) रहे।

भाजपा कर्नाटक के महामंत्री (संगठन) रहते हुए श्री संतोष ने तमिलनाडु और केरल में पार्टी को सशक्त करने में भी अपनी भूमिका निभाई। दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा उन्होंने कई अन्य राज्यों में भी काम किया,

जिनमें उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हैं।

साल 1993 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनने के बाद श्री बी.एल. संतोष ने जमीनी स्तर पर संघ में कई जिम्मेदारियां निभाईं, जैसे नगर प्रचारक, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, शिमोगा में भाजपा के महामंत्री (संगठन) की जिम्मेदारी शामिल हैं।

रा.स्व.संघ में आने से पहले पेशे से एक इंजीनियर श्री संतोष को पढ़ने का शौक है, विशेष रूप से पर्यावरण विज्ञान, राष्ट्रीय सुरक्षा

जीवन वृत्त

नाम : बी.एल. संतोष

जन्मस्थान : चामाराजनगर

शिक्षा : बी.ई. (इंस्ट्रुमेंटेशन टेक्नालॉजी),
गवर्नमेंट बी.डी.टी. कॉलेज ऑफ
इंजीनियरिंग, दावणगेरे, कर्नाटक

पेशा : डिजाईन इंजीनियर के रूप में
एक टेलीकम्युनिकेशन फॉर्म में ढाई साल
कार्यरत।

संघ दायित्व : - बेंगलुरु नगर कार्यवाह
रहे।

- जून 1993 से प्रचारक जीवन शुरू किया।
- मैसूर सिटी के एक वर्ष तक नगर प्रचारक रहे।
- 3 वर्षों तक मैसूर के जिला प्रचारक के रूप में कार्य किया।
- शिमोगा के 2 वर्ष तक जिला प्रचारक रहे।
- साढ़े तीन सालों तक बंगलुरु में सह विभाग प्रचारक रहे।
- शिमोगा के साढ़े चार साल तक विभाग प्रचारक रहे।

भाजपा में दायित्व : - कर्नाटक राज्य के
महामंत्री (संगठन) के रूप में 8 वर्षों तक
कार्य किया।

- 2014 से भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन
महामंत्री (संगठन) के दौरान दक्षिण
भारत का प्रवास।

अध्ययन : - वाटर और सोलिड वेस्ट
मैनेजमेंट पर अध्ययन।

- आंतरिक और बाह्य सुरक्षा स्थितियों पर अध्ययन।
- प्राचीन और आधुनिक विश्व को भारत का योगदान पर अध्ययन।

विशेष: कन्नड़, अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल,
तुलु भाषाओं के जानकार।

और राजनीतिक सिद्धांत जैसे विषय सदैव उनके पसंदीदा रहे हैं।

श्री बीएल संतोष धाराप्रवाह पांच भाषाएं बोल सकते हैं - अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल और तुलु।

श्री रामलाल मेरे जैसे बहुत से लोगों के लिए पितातुल्य: बी एल संतोष

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बीएल संतोष ने कहा कि श्री रामलाल उनके जैसे कई लोगों के लिए पिता तुल्य हैं।

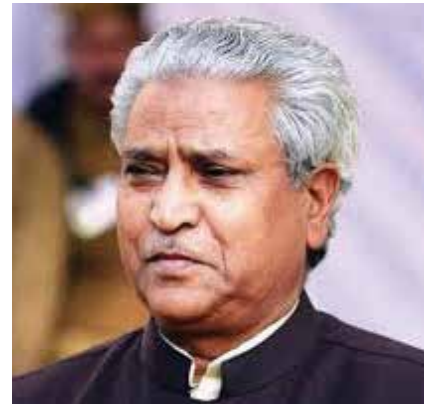
श्री बी.एल. संतोष ने नई जिम्मेदारी लेते हुए श्री रामलाल द्वारा सालों तक पार्टी की सेवा को सराहते हुए ट्वीट किया:

“2006 से रामलालजी के साथ सीखने को 12 साल मिले .. मैं उनके साथ राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनियुक्त था.. शांत, रचनात्मकता, विवरण पर ध्यान देना उनकी पहचान थी। वह मेरे जैसे कई लोगों के लिए पितातुल्य रहे। संघ कार्य पर वापस। आप को शुभकामनाएं। हम आपको याद करेंगे।

श्री रामलाल सघन प्रवास करने और नियमित रूप से संगठनात्मक बैठक लेने के लिए जाने जाते हैं। सार्वजनिक जीवन में उनकी सादगी भरी शैली ने अनेक कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। श्री रामलाल पार्टी के सबसे लंबे समय तक कार्यरत राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) रहे हैं और उनका कार्यकाल पार्टी और संगठन के बीच सहज समन्वय के लिए जाना गया।

उनकी छवि एक अभिभावक वाली रही, उन्होंने प्रत्येक कार्य को एक सहजता से संभाला। पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता चाहे वह पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हों या नवागंतुक, आसानी से उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने विचारों को उनके साथ साझा कर सकते हैं।

राजस्थान के भरतपुर जिले के डीघ में 22 दिसंबर, 1952 को जन्म लेने वाले श्री रामलाल एक विधि स्नातक हैं और 1974 में रा.स्व.संघ में प्रचारक के रूप में शामिल हुए थे। 2000 में बूज, मेरठ और उत्तरांचल के क्षेत्र प्रचारक बनने से पहले उन्होंने संघ में कई अन्य जिम्मेदारियां निभाईं। उन्होंने आपातकाल विरोधी आंदोलन में बाबू जयप्रकाश नारायण के



साथ भाग लिया और मेरठ जेल में आठ महीने तक उनके साथ रहे। उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे और यहां तक कि उनका पूरा परिवार समाज के शैक्षिक और सामाजिक कल्याण कार्यों के लिए समर्पित रहा है। श्री रामलाल ने 2006 में भाजपा में प्रवेश किया और उन्हें 2007 में राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) का दायित्व मिला।

श्री रामलाल जो आपातकाल के दिनों से भी पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय थे, 13 जुलाई, 2019 को अपनी मातृ संगठन में वापस आ गए हैं और अब वे संघ के 'अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख' के रूप में कार्य करेंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) के रूप में, उन्होंने तीन भाजपा अध्यक्षों के साथ काम किया: श्री राजनाथ सिंह, श्री नितिन गडकरी और श्री अमित शाह। अब जबकि श्री रामलाल भाजपा से वापस संघ में जा रहे हैं, वह पार्टी के इतिहास में ऐसे समय में इस पद पर रहें, जब पार्टी अपने चरम पर है। दायित्व बदलने पर श्री रामलाल ने कहा :

“दायित्व परिवर्तन संघ में स्वाभाविक प्रक्रिया है। दायित्व व क्षेत्र कोई भी हो, सभी का एक ही कार्य है भारत माता की सेवा। कुछ अच्छा करने का निमित्त यदि बना तो उसमें आप सभी का स्नेह व सहयोग बड़ा कारण है। आपकी शुभेच्छाएं मेरे लिए संबल है। ■

राधामोहन सिंह भाजपा के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त

भा रतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 19 जुलाई को संगठनात्मक चुनाव के संचालन के लिए सांसद एवं पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह को राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया।

साथ ही, उत्तर प्रदेश से सांसद सर्वश्री विनोद सोनकर, महाराष्ट्र के पूर्व सांसद



हंसराज अहीर और कर्नाटक के विधायक सी.टी. रवि राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए।

भाजपा की पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संगठनात्मक चुनाव के संचालन के लिए राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। ■

चंद्रकांत दादा पाटिल बने महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

भा रतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 16 जुलाई 2019 को महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री चंद्रकांत दादा पाटिल को पार्टी की महाराष्ट्र इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। श्री पाटिल वर्तमान में महाराष्ट्र प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। श्री पाटिल को केंद्र सरकार में मंत्री श्री राव साहेब दानवे पाटिल की जगह प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ■



मुंबई प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने मंगल प्रभात लोढ़ा

भा रतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 16 जुलाई 2019 को विधायक श्री मंगल प्रभात लोढ़ा को मुंबई इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। वह मुंबई इकाई के निवर्तमान अध्यक्ष श्री आशिष शेलार का स्थान लेंगे जिन्हें हाल ही में राज्य सरकार में स्कूली शिक्षा मंत्री बनाया गया है। ■



उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने स्वतंत्र देव सिंह

भा रतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 16 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री स्वतंत्र देव सिंह को पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। श्री सिंह अनेक संगठनात्मक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं। वे 2001 में भारतीय जनता युवा मोर्चा, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष



रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने भाजपा, उत्तर प्रदेश के महामंत्री का दायित्व निभाया। वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं। निवर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेन्द्र नाथ पांडे के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद यह नियुक्ति की गयी है। ■

अदालतों में 61 प्रतिशत कम हुई अप्रत्यक्ष कर मामलों की संख्या

वित्त वर्ष 2018-19 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.37 लाख करोड़ रुपये

दे श की अदालतों में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित लंबित अपीलीय मामलों की संख्या करीब दो साल में 61 प्रतिशत घटकर 1.05 लाख रह गई। यह जानकारी 23 जुलाई को संसद को दी गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 30 जून, 2017 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरणों में अपील के लंबित मामलों की कुल संख्या 2,73,591 थी जो 31 मार्च, 2019 को घटकर 1,05,756 रह गई। इस प्रकार इनमें 61 प्रतिशत की जोरदार गिरावट आई है।

प्रत्यक्ष करों के संबंध में, 31 मार्च, 2019 तक, आयुक्त (अपील) के समक्ष 3.41 लाख मामले लंबित थे, जबकि



92,205 मामले आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष लंबित थे। इसके अलावा, 31 दिसंबर, 2018 तक 43,224 और 6,188 प्रत्यक्ष कर से जुड़े

मामले क्रमशः उच्च अदालत और उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित थे।

एक अलग उत्तर में श्री ठाकुर ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में अनंतिम प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.37 लाख करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2017-18 में 10.02 लाख करोड़ रुपये और वर्ष 2016-17 में 8.49 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। वर्ष 2018-19 में अनंतिम अप्रत्यक्ष कर संग्रह (जिसमें केंद्रीय जीएसटी, एकीकृत जीएसटी, मुआवजा उपकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर शामिल हैं) 9.37 लाख करोड़ रुपये रहा, जो वर्ष 2017-18 में एकत्र किये गये 9.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। वर्ष 2016-17 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह 8.61 लाख करोड़ रुपये रहा था। ■

देश में सांप्रदायिक घटनाओं में आयी गिरावट

भा जपानीत केंद्र की राजग सरकार के कुशल प्रशासन के चलते पिछले कुछ सालों में देश में सांप्रदायिक तनाव में कमी आयी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 24 जुलाई को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में खुफिया ब्यूरो (आईबी) के आंकड़ों के हवाले से बताया कि 2013 में सांप्रदायिक घटनाओं के 823 मामले दर्ज किये गये, जबकि 2018 में इनकी संख्या घटकर 708 रह गयी।

श्री रेड्डी ने कहा, “यह वास्तविकता है कि देश में सांप्रदायिक घटनाओं में कमी आयी है। सांप्रदायिक हिंसा या किसी अन्य प्रकार की हिंसा के प्रति हमारी सरकार का इरादा ‘जीरो टॉलरेंस (कतई बर्दाश्त नहीं करने)’ की नीति का पालन करने का है।”

सांप्रदायिक हिंसा के मामलों का रिकॉर्ड दर्ज करने और इन आंकड़ों के स्रोत से जुड़े पूरक प्रश्न के जवाब में श्री रेड्डी ने बताया

कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2014 से देश में सांप्रदायिक घटनाओं का रिकार्ड दर्ज करना शुरु किया है। हालांकि इसे 2017 में बंद करना पड़ा, क्योंकि पहले (आईबी) इन मामलों के जो रिकार्ड दर्ज करती थी उसमें संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा दर्ज प्राथमिकता से भिन्नता पायी गयी। इस पर राज्य सरकारों द्वारा रिकार्ड में भिन्नता पर आपत्ति दर्ज करने के कारण एनसीआरबी ने 2017 में इसका रिकार्ड दर्ज करना बंद कर दिया।

सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिये अलग से कानून बनाने के सवाल पर उन्होंने मौजूदा कानून को पर्याप्त बताते हुये कहा कि सांप्रदायिक तनाव और हिंसा से निपटने के लिये नया कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को इस बारे में खुफिया जानकारियां साझा करने के साथ साथ परामर्श भी जारी करती रहती है। ■

नरेन्द्र मोदी भारत में 2019 के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति हैं और विश्व में पसंदीदा पुरुषों की सूची में वे छठे स्थान पर हैं। गौरतलब है कि ब्रिटेन की एक इंटरनेट मार्केट रिसर्च और डाटा एनलिटिक्स फर्म YouGov के हालिया सर्वे में यह बात सामने आई है। YouGov की सूची में श्री मोदी एक मात्र भारतीय राजनेता हैं। पिछले साल श्री मोदी इस सर्वे की विश्व सूची में आठवें स्थान पर थे और इस साल वे दो पायदान उपर हैं। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता न केवल भारत में, बल्कि विश्व में भी निरंतर बढ़ती जा रही है।



पांच साल में गृह मंत्रालय के 1083 कर्मचारी बर्खास्त

भाजपा नीत केंद्र की राजग सरकार ने 17 जुलाई को बताया कि पिछले पांच साल में कुल 1083 कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल के दौरान अनुशासन नियमों के तहत मंत्रालय के कुल 1083 कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रभावी अनुशासन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सरकारी सेवा से बर्खास्त करने सहित किसी प्रकार का दंड लगाने से पहले सरकारी कर्मचारियों को बचाव के पर्याप्त मौके मुहैया कराए जाते हैं।

उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) के अंतर्गत चालू मार्गों की संख्या बढ़कर 186 हुई

दुर्गापुर आरसीएस उड़ान के मानचित्र पर नवीनतम हवाई अड्डा

क्षेत्रीय सम्पर्क योजना या उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) के अंतर्गत हाल ही में 12 मार्ग चालू किये गये हैं। इसके साथ ही उड़ान के अंतर्गत स्वीकृत कुल 706 मार्गों में से चालू मार्गों की कुल संख्या बढ़कर 186 (8 पर्यटन आरसीएस मार्गों सहित) हो गई है। इसके अलावा दुर्गापुर हवाई अड्डा इस योजना के अंतर्गत चालू होने वाला 40वां हवाई अड्डा बन गया है।

गौरतलब है कि नागर विमानन मंत्रालय ने हवाई सम्पर्क को प्रोत्साहन देने और हवाई यात्रा को आम जनता के लिए किफायती बनाने के लिए 21 अक्टूबर, 2016 को उड़े देश का आम नागरिक का शुभारंभ किया था। तब से निविदा के 3 (तीन) चरण पूरे हो चुके हैं। पहली आरसीएस-उड़ान

का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री ने 27 अप्रैल, 2017 को शिमला में किया था।

भारत में छोटे शहरों को जोड़ने वाली आरसीएस उड़ान शुरू करने के लिए 106 आरसीएस हवाई अड्डों/वाटर एरोड्रोम (76 उपयोग में न आने वाले, 20 क्षमता से कम उपयोग वाले और 10 वाटरड्रोम) तथा 31 हेलीपोर्ट की पहचान की गई है। 46 पर्यटन आरसीएस मार्गों सहित 706 आरसीएस मार्ग उड़ान के तहत 19 चुनिंदा एयरलाइन ऑपरेटरों को प्रदान किये गये हैं। आरसीएस उड़ानें 40 आरसीएस (23 उपयोग में न आने वाले और 17 क्षमता से कम उपयोग वाले) से शुरू की गई हैं और दुर्गापुर आरसीएस उड़ान के मानचित्र पर नवीनतम हवाई अड्डा है। ■



कुलभूषण जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर फिर से विचार करे पाकिस्तान: अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत

अं

तरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने 17 जुलाई को फैसला सुनाया कि पाकिस्तान को भारतीय नागरिक श्री कुलभूषण जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर फिर से विचार करना चाहिए। यह भारत की बड़ी जीत है।

भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर फांसी की सजा सुनाई थी। इस पर भारत में काफी गुस्सा देखने को मिला था। फैसले को पढ़ते हुए अदालत के अध्यक्ष जज अब्दुलकावी अहमद यूसुफ ने श्री कुलभूषण सुधीर जाधव को दोषी ठहराये जाने और सजा पर फिर से विचार करने का आदेश दिया।

आईसीजे के जज यूसुफ के नेतृत्व में 15 सदस्यीय पीठ ने भारत और पाकिस्तान की मौखिक दलीलों को सुनने के बाद 21 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मामले की कार्यवाही पूरी होने में दो साल दो महीने का समय लगा। भारत ने श्री जाधव तक बार-बार कंसुलर एक्सेस नहीं मिलने पर पाकिस्तान द्वारा वियना समझौते के प्रावधानों का घोर उल्लंघन करने के लिए आठ मई, 2017 को आईसीजे का रुख किया था।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आईसीजे के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने ट्वीट किया कि आईसीजे के फैसले का हम स्वागत करते हैं।

सत्य और न्याय की हमेशा रक्षा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि आईसीजे को इस निर्णय के लिए बधाई, क्योंकि इस पर फैसला करने के लिए तथ्यों का अध्ययन करना पड़ा होगा। मुझे विश्वास है कि श्री कुलभूषण जाधव को न्याय मिलेगा। हमारी सरकार, भारत के हर नागरिक की सुरक्षा और देखभाल के लिए हमेशा काम करेगी। हर भारतीय को बचाया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आईसीजे के निर्णय पर कहा, 'भारत के लिए यह बड़ी कूटनीतिक जीत है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और हरीश साल्वे को बधाई देता हूँ। इन्होंने ही आईसीजे के सामने इस मुद्दे को ठीक ढंग से रखा और साबित किया कि कुलभूषण निर्दोष हैं। हम चाहते हैं कि मां भारती का बेटा अपने देश वापस आए।'

आईसीजे के इस निर्णय का पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने भी स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि यह भारत के लिए बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के इस फैसले का सम्मान करती हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा है कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी को भी शुक्रिया कहती हूँ। उन्हीं के नेतृत्व में कुलभूषण जाधव के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सामने उठाया गया। ■

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने की प्रधानमंत्री उज्वला योजना की तारीफ, बताया सामाजिक-आर्थिक उपलब्धि

अं

तरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी उज्वला योजना की 19 जुलाई को सराहना की। उसने कहा कि यह पर्यावरण को स्वच्छ बनाने तथा महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर करने की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि है।

आईईए के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने कहा, "वर्ष 2020 तक देशभर में एलपीजी उपलब्ध कराना बड़ी उपलब्धि है। यह ऊर्जा का मुद्दा नहीं है बल्कि यह एक आर्थिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है।"

प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बलिया में एक मई 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य गरीब परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराकर महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बनाना है। अभी तक इस योजना के तहत करीब 7.40 करोड़ कनेक्शन दिये जा चुके हैं। योजना के तहत 2020 तक आठ करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य है।

बिरोल ने कहा कि ग्रामीण परिवारों में रसोई में लकड़ी, उपले और

दूसरे कृषि अपशिष्टों का इस्तेमाल किया जाने से सांस संबंधी बीमारियों का मुख्य कारण है। एलपीजी से स्वच्छ पर्यावरण मुहैया कराने में मदद मिल रही है।

उन्होंने कहा, "उज्वला महज ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धि नहीं है बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक उपलब्धि भी है।" विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी पिछले साल इस योजना की तारीफ की थी। बिरोल ने कहा कि भारत ने पिछले साल सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया। जल्दी ही सभी घरों में बिजली पहुंच जाएगी। यह एक बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने कहा कि भारत ने 2022 तक सौर ऊर्जा एवं अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 175 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य तय किया है। यदि यही रफ्तार रही तो लक्ष्य को संशोधित कर बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही जैव ईंधन के इस्तेमाल पर अधिक जोर देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तेल एवं गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के साथ ही इन कदमों से देश को आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। ■

राजनीतिक विकेंद्रीकरण का ही दूसरा नाम प्रजातंत्र है



दीनदयाल उपाध्याय

जब कोई व्यक्ति आजादी चाहता है तो वह सुरक्षा की मांग भी करता है। एक व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए आपको दूसरे की कुछ आजादी कम करनी पड़ती है। इस प्रकार व्यावहारिक रूप से स्वतंत्रता का अर्थ है कुछ अंकुश लगाना। ये बंदिशें क्या होंगी, यह स्थितियों की आवश्यकता पर निर्भर है। परंतु एक व्यवस्थित समाज में हर व्यक्ति को इन सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। जिस तरह के रोक लगाने की जरूरत पड़ सकती है, उनका अनुमान किया जाना चाहिए और व्यक्ति विशेष को गतिविधि के लिए अधिकतम आजादी दी जानी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि व्यक्ति की सुरक्षा के नाम पर व्यक्ति की उद्यमशीलता नष्ट न हो जाए और न ही अत्यधिक सुरक्षा उसके विकास की क्षमताओं को पंगु बना दे। इस प्रकार एक संतुलन बनाना आवश्यक है। हम इसे 'मर्यादाओं का निर्माण' कहते हैं। 'मर्यादाएं' व्यक्ति विशेष का समाज में दायित्व, समाज में जीवन-मूल्य निर्धारित करती हैं।

शक्तियों का अधिकाधिक केंद्रीकरण ही व्यक्तियों की स्वतंत्रता को नष्ट करता है। बढ़ते हुए केंद्रीकरण पर रोक लगानी चाहिए। वंशानुगत शासकों के हाथ में अथवा तानाशाहों के हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण सदा लोगों को राजनीतिक आजादी से वंचित करता है। यह हो सकता है कि एक अच्छा शासक या परोपकारी तानाशाह, लोकहित को सर्वोपरि रखे, परंतु यह भी राजनीतिक

क्षेत्र में लोगों की पहल को समाप्त कर सकता है। एक राष्ट्रीय सरकार, जिसे जनता ने मतदान से चुना है, जरूरी नहीं कि राजनीतिक प्रजातंत्र को सुनिश्चित करे, यदि वहां जरूरत से ज्यादा शक्तियों का केंद्रीकरण और एकीकरण है। सब कुछ विकेंद्रित करना होगा। विकेंद्रीकरण का अर्थ सत्ता का हस्तांतरण अथवा प्रत्यायोजन नहीं है। यह तो पुराने अडयार के वट वृक्ष की तरह है, जिसमें जड़ें और तने में भेद नहीं दिखाई पड़ता। राष्ट्रीय सरकार को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने दायित्व निभाने चाहिए तथा नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में कम-से-कम हस्तक्षेप करना चाहिए। ये सब अनिवार्य रूप से स्थानीय सरकार के जिम्मे रहना चाहिए। राजनीतिक विकेंद्रीकरण का ही दूसरा नाम प्रजातंत्र है।

एकाधिकारवाद एवं समूहवाद

राजनीतिक क्षेत्र की तरह आर्थिक क्षेत्र में भी एकाधिकारवाद अथवा समूह तंत्र द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण आर्थिक प्रजातंत्र के लिए घातक है। बड़े एकाधिकारवादी अथवा समूहवादी जनता को आर्थिक आजादी से वंचित कर देते हैं। वे मूल्य नियंत्रित करते हैं और मूल्यों, विज्ञापनों तथा विपणन कला द्वारा मनुष्य की उपयोग की आजादी को प्रभावित करते हैं। मुक्त व्यापारी कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जब कभी आप कुछ खरीदते हैं, तब आप आर्थिक क्षेत्र में अपना मत प्रयोग करते हैं। उपभोक्ता की पसंद उद्यमी के निर्णयों को संचालित करती है। यह बात उस सीमा तक सत्य है, जब तक ये उद्यम एक सीमा में विकसित होते हैं। परंतु उससे आगे आर्थिक मतदान, साम्यवादी देश में मतदान जैसा ही होता है। मतदान वहां अनिवार्य है परंतु मत सरकारी प्रत्याशी को देना होता है।

जब हम पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो क्या अपने आर्थिक मतदान की आजादी का प्रयोग करते हैं? मूल्य निर्धारण भी वस्तु के उत्पादन या उपभोग पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सुदूर दक्षिण अमरीका शहर में बैठे लोगों को प्रशासनिक निर्णय पूरे करता है।

इसीलिए यदि हम आर्थिक प्रजातंत्र बचाना चाहते हैं तो हमें विकेंद्रीकरण चाहिए। राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने एक बार कहा था- 12.4 करोड़ की आबादी की 'आर्थिक जिंदगी को लगभग 600 कॉरपोरेशंस नियंत्रित करते हैं, जिनके पास अमरीका के दो-तिहाई उद्योग हैं तथा शेष 1/3 भाग एक करोड़ व्यापारियों में बंटता है।' (लुकिंग फारवर्ड, 1937)। यही स्थिति इंग्लैंड की थी, जहां कुल आय का आधा भाग 12 प्रतिशत आबादी को और 1/3 भाग 3 प्रतिशत आबादी को जाता है। प्राप्तकर्ताओं को कम आय अधिक परिश्रम से प्राप्त थी और बहुत बड़ी आय बिना श्रम के अथवा बहुत कम श्रम से। इतालवी अर्थशास्त्री लोरिया ने सारगर्भित वाक्य में स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा- 'कुछ बिना कुछ किए जीते हैं और कुछ काम करते हैं, जीते नहीं।'

पूर्ण आर्थिक प्रजातंत्र

उत्पादन की आजादी के लिए जरूरी है कि आपके पास काम हो। यदि करने के लिए काम न मिले तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसी अनुपात में उपभोक्ता की आजादी कम न हो, काम के बदले राज्य को अथवा अन्य सामाजिक संगठनों को भत्ता देना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा के उपाय और पूर्ण रोजगार आर्थिक प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य हैं। आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण ही सारे आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करवा सकता है।

प्रजातंत्र के सिद्धांत की रक्षा के लिए विकेंद्रीकरण के साथ-साथ, शक्तियों के पृथक्कीकरण की भी आवश्यकता है। किसी भी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक संस्था को अपने निजी क्षेत्र से बाहर अधिकार नहीं मिलने चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को कार्य करना चाहिए तथा एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे क्षेत्र को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। राज्य, जो कि एक राजनीतिक संस्था है, उसे आर्थिक दायित्व नहीं संभालना चाहिए और जो अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं, उनके पास राजसत्ता नहीं होनी चाहिए। धर्माधिकारी को राज्याधिकारी नहीं बनना चाहिए। 'खिलाफत' और 'पोप' का पद सभी क्षेत्रों में प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत का विरोधी है। केवल मनुष्य में ही सारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संस्थाएं समाहित एकीकृत होती हैं, अन्य किसी स्थान पर इन्हें परस्पर आच्छादित नहीं होना चाहिए।

औद्योगिक क्रांति के पश्चात् जिस तरह पूंजीवाद का विकास हुआ है, उसमें अर्थसत्ता का केंद्रीकरण हुआ है और इसके कारण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से राजनीतिक तथा अन्य संस्थाएं प्रभावित हुई हैं।

इस प्रकार आर्थिक प्रजातंत्र रहित राजनीतिक प्रजातंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, जिसने प्रजातंत्र के प्राण हर लिए हैं और यह प्राण रहित शरीर मात्र रह गया है। इस व्यवस्था का लक्ष्य आर्थिक मनुष्य है। इसमें उत्पादन पर बल है और वह भी लाभ मात्र के लिए। पैसा पूजा जाने लगा है और वही मूल्यांकन का आधार बना है। इस प्रकार अर्थसत्ता कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो गई है और शेष समाज पर एक ही धुन सवार है, 'पैसा कमाना।'

समाजवाद इसलिए भी प्रजातंत्र विरोधी है, क्योंकि इसमें सत्ता का केंद्रीकरण राज्य

सत्ता में है। एक समाजवादी व्यवस्था में राज्य केवल राजनीतिक अथवा अर्सेनिक संस्था नहीं होता बल्कि आर्थिक संस्था भी होता है। राज्य की आर्थिक शक्ति किसी एकाधिकारी औद्योगिक साम्राज्य की शक्तियों से कहीं अधिक होती है, जिसे उद्योगपति और वित्तपोषक नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के मेल से शक्ति बढ़ जाती है। इस मिलन की घातक शक्ति कई हज़ार गुणा बढ़ जाती है। गांधीजी ने जब यह कहा कि राज्य की शक्ति में वृद्धि को अत्यधिक भय से देखना चाहिए, क्योंकि देखने में भले ही सर्वाधिक कल्याणकारी दिखे (कल्याणकारी राज्य के नाम पर), न्यूनतम

उत्पादन की आजादी के लिए जरूरी है कि आपके पास काम हो। यदि करने के लिए काम न मिले तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसी अनुपात में उपभोक्ता की आजादी कम न हो, काम के बदले राज्य को अथवा अन्य सामाजिक संगठनों को भत्ता देना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा के उपाय और पूर्ण रोजगार आर्थिक प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य हैं। आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण ही सारे आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करवा सकता है।

शोषण के नाम पर यह मानवता को सबसे बड़ी हानि उसके व्यक्तित्व का विनाश करके पहुंचती है, जो कि सारे विकास का मूलाधार है। व्यक्ति में आत्मा होती है, परंतु राज्य तो आत्म रहित मशीन ही है।

साम्यवाद आत्मघातक है

प्रिंस क्रोपाटकिन' ने बहुत पहले 1904 में भांप लिया था कि समाजवाद बढ़ा हुआ खतरा है, जब उसने लिखा था, "क्या वे युग की मुख्य प्रवृत्ति विकेंद्रीकरण, स्वशासन और सहमति का अनुसरण करेंगे या फिर इसके विपरीत चलते हुए विनष्ट सत्ता को पुनः स्थापित करेंगे।" बाद में 1919 में यूरोप के मजदूरों को एक पत्र में उन्होंने लिखा, "आपको

यह बताना मेरा कर्तव्य है कि अत्यधिक केंद्रित राज्य सत्ता पार्टी के लौह नियंत्रण की तानाशाही में साम्यवाद के आधार पर साम्यवादी गणराज्य स्थापित करने का प्रयास असफल होने के लिए अभिशप्त है। हम रूस में किस तरह साम्यवाद को जारी न रखा जाए, यह सीख रहे हैं। जब देश एकदलीय तानाशाही द्वारा शासित होता है तो उसमें मजदूर तथा किसान समितियां अपना पूरा महत्त्व खो देती हैं। यहां (रूस) ऐसी भयंकर नौकरशाही का जन्म हुआ है, जो फ्रांसीसी नौकरशाही, जिसे मुख्य मार्ग पर तूफान से गिरे एक पेड़ को बेचने के लिए पचास लोगों की जरूरत पड़ती है, उसके सामने राई मात्र है। इस प्रकार राज्य-पूंजीवादी समाज का कोई विकल्प नहीं है। यह व्यवस्था समाज को जो सुरक्षा प्रदान करने का वादा करती है, उसके बदले वह व्यक्ति की सोचने, काम करने और संगठित होने की आजादी छीन लेती है। यद्यपि दोनों व्यवस्थाएं व्यक्तिगत आजादी और मानव कल्याण का वादा करती हैं, परंतु वास्तव में कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करतीं और अंततः ऐसी स्थिति पैदा करती हैं, जिसमें व्यक्तिगत

आजादी और प्रजातांत्रिक अधिकार महत्त्वहीन होकर रह जाते हैं। वर्तमान में हम केवल प्रजातांत्रिक आदर्शों की रक्षा के लिए चिंतित हैं और बिना संकोच के यह कहा जा सकता है कि इसकी प्राप्ति विकेंद्रित समाज और शक्तियों तथा कार्यों के पृथक्कीकरण से ही संभव है। इसलिए नियोजन का लक्ष्य मुख्य रूप से होना चाहिए —

1. सुरक्षा क्षमता बढ़ाई जाए,
2. राजनीतिक प्रजातंत्र का संरक्षण और परिवर्धन हो,
3. 'आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना', जो नागरिकों को काम करने का अधिकार और न्यूनतम उपभोग सुरक्षा प्रदान करके सुनिश्चित की जा सकती है। ■

-ऑर्गेनाइज़र, अगस्त 20, 1960
(अंग्रेज़ी से अनूदित)

नहीं रहे मांगोराम गर्ग

(23 नवम्बर, 1936 – 21 जुलाई, 2019)

दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वजीरपुर विधानसभा से विधायक रहे श्री मांगोराम गर्ग का 21 जुलाई को दिल्ली में निधन हो गया। वह 83 साल के थे।

जीवन परिचय

श्री मांगोराम गर्ग का जन्म 23 नवम्बर, 1936 को हरियाणा के नरवाना तहसील के कुराड़ गांव में हुआ था। गर्ग जी बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहे। उन्होंने अपना शरीर चिकित्सक शोध के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया था।

युवा अवस्था के समय से ही जनसंघ से जुड़े श्री गर्ग, स्वामी विनोबा भावे के स्वावलम्बन आंदोलन में भाग लिया। समालखा रेलवे स्टेशन पर आजादी से पूर्व बाल्यकाल में श्री गर्ग ने यात्रियों को पानी पिलाकर सेवा के काम की शुरुआत की।

श्री मांगोराम गर्ग हमेशा कहा करते थे कि राजनीति सेवा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। श्री गर्ग ने दो पुस्तकें भी लिखी- एक 'सेवा का सच' और दूसरी 'महाकलेश्वर'। श्री गर्ग दैनिक दिनचर्या को डायरी में लिखकर अपने काम के लेखा-जोखा का स्वयं मूल्यांकन करते थे।

जिला अध्यक्ष, दिल्ली भाजपा प्रदेश महामंत्री, प्रदेश कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद श्री गर्ग 1997 में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष बने। इनके नेतृत्व में 1999 में भाजपा ने दिल्ली की सभी सातों सीटों पर विजय प्राप्त की। श्री मांगोराम गर्ग लगातार पांच सालों (1997-2002) तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2003 से 2008 तक वे वजीरपुर से दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे। वे 2002 से 2014 तक राष्ट्रीय आजीवन सहयोग निधि के प्रमुख रहे। श्री गर्ग 2014 से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय निर्माण समिति के सदस्य के रूप

शोक संदेश

मांगोरामजी के निधन से पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। वे निःस्वार्थ भाव से काम करते थे। वे जमीनी स्तर से जुड़े नेता थे। मांगोरामजी समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। श्री गर्ग ने दिल्ली की जनता और पार्टी के लिए जो काम किया है वह वर्षों तक याद किया जाता रहेगा। श्री मांगोराम गर्ग का दिल्ली से गहरा नाता था और उन्हें शहर के लोगों की निःस्वार्थ भाव से सेवा करते थे। उन्होंने दिल्ली में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका निधन दुःखद है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।

- श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मांगोराम गर्ग का निधन भाजपा परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। दिल्ली की जनता की सेवा और संगठन के लिये समर्पित मांगोराम का जीवन सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता है।

- श्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

मांगोराम गर्ग जी के निधन से मन अत्यंत दुःखी है। उनका निधन संगठन के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।

- श्री जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष



में काम देख रहे थे, जिसके तहत भाजपा के प्रदेशों एवं जिलों में कार्यालय निर्माण का काम किया जा रहा था।

श्री मांगोराम गर्ग ने अनेक सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का गठन करके सेवा भाव का काम किया। उनमें प्रमुख संस्थाएं- धर्मयात्रा महासंघ, अग्रवाल निष्काम सेवा

ट्रस्ट हरिद्वार, आदर्श रामलीला कमेटी, आदर्श शिक्षा संस्थान, आदर्श धर्माथ संस्थान, आदर्श विवाह समिति, अग्रवाल वेलफेयर सोसायटी, एकता चेरिटेबल ट्रस्ट गोवर्धन, शिव कृष्णा सेवा ट्रस्ट वृंदावन, नीलकंठ धाम हरिद्वार, गंगामाता चेरिटेबल ट्रस्ट हरिद्वार शामिल हैं। ■

आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिये कठोर कानून जरूरी: अमित शाह

लोकसभा ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 24 जुलाई को पारित कर दिया। विधेयक पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य आतंकी अपराधों की त्वरित जांच और अभियोजन की सुविधा प्रदान करना और आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान प्रदान करना है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यूएपीए या किसी अन्य कानून में व्यक्तिगत आतंकवादी को नामित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, जब किसी आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उसके सदस्य एक नया संगठन बनाते हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि जब कोई व्यक्ति आतंकवादी कार्य करता है या भाग लेता है, आतंकवाद को पोषण देने में मदद करता है, आतंकवाद की अभिव्यक्ति देने के लिए धन मुहैया कराता है अथवा आतंकवाद के साहित्य को या उसकी थ्योरी को युवाओं के मन में भरने का काम करता है ऐसे दोषी व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करना आवश्यक है।

श्री शाह ने कहा कि आतंकवाद व्यक्ति की मंशा का होता है, आतंकवाद संस्थाओं में नहीं होता है। इसलिए आतंकवाद से जुड़े व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने के प्रावधान की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसके लिये संयुक्त राष्ट्र और अन्य राष्ट्रों के समान प्रावधान किये गये हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि संशोधन में कानून के दुरुपयोग रोकने के लिए बहुत सारी सावधानियां रखी गई हैं। संशोधन में प्रस्तावित प्रावधानों के दुरुपयोग के बारे में सदस्यों के बीच भय को दूर करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह संशोधन व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने की केवल तभी अनुमति देता है, जब कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया के बाद पर्याप्त सबूत हों। गिरफ्तारी या जमानत प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा।

एनआईए के निरीक्षक स्तर पर अपराधों की जांच करने के संबंध में उनका कहना था कि विभिन्न स्तरों पर एनआईए में केसों का रिव्यू किया जाता है, इसलिए निरीक्षक के द्वारा जांच करने पर भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इस संशोधन के पीछे उद्देश्य यह है कि जांच जल्दी हो।

श्री अमित शाह ने सभी सदस्यों से संशोधन के समर्थन में

आने की अपील करते हुए कहा कि यह कानून सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादियों से चार कदम आगे रखने के लिए है।

इससे पूर्व लोक सभा में बोलते हुए आतंकवाद के प्रति सरकार की शून्य सहिष्णुता की नीति को दोहराते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने पूरे देश में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। पाकिस्तान द्वारा विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में राज्य प्रायोजित आतंकवाद से दृढ़ता और प्रभावी ढंग से निपटा गया है। इसके अलावा आतंकवाद में बहुत कमी आई है। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है।

श्री नित्यानंद ने बताया कि वर्तमान में यूएपीए की धारा 25 के अनुसार आतंकवाद की कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति को केवल उस राज्य के डीजीपी द्वारा लिखित अनुमोदन के साथ जप्त किया जा सकता है, जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है। कई बार आतंकी विभिन्न राज्यों में अपनी संपत्ति रखते हैं। ऐसे मामलों में अलग-अलग राज्यों के डीजीपी की मंजूरी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और जिसके कारण होने वाली देरी से अभियुक्तों की संपत्ति आदि को स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए जल्द से जल्द आतंकवाद की कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्तियों को जप्त करना आवश्यक है। यह संशोधन डीजी एनआईए को ऐसी संपत्ति को जप्त करने का अधिकार देता है जो एनआईए द्वारा की जा रही जांच के संबंध में आतंकवाद की आय का प्रतिनिधित्व करती है।

श्री राय ने यह भी बताया कि वर्तमान में यूएपीए की धारा 43 के अध्याय IV और अध्याय VI के अनुसार डीएसपी या समकक्ष के पद से नीचे के अधिकारी यूएपीए के तहत अपराधों की जांच करने के लिए सक्षम नहीं हैं। एनआईए को डीएसपी की कमी का सामना करना पड़ रहा है और मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। वर्तमान में एनआईए के पास 57 स्वीकृत पदों के मुकाबले 29 डीएसपी और 106 स्वीकृत पदों के मुकाबले 90 निरीक्षक हैं। एनआईए के निरीक्षकों ने इन अपराधों की जांच करने के लिए पर्याप्त प्रवीणता हासिल कर ली है और इस प्रकार इस खंड में संशोधन यूएपीए के अध्याय IV और अध्याय VI के तहत दंडनीय अपराधों की जांच के लिए एनआईए के निरीक्षकों को सक्षम बनाने के लिए किए जा रहे हैं।

इस संशोधन में परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन हेतु अंतरराष्ट्रीय कंवेशन (2005) को सेकेंड शिड्यूल में शामिल किया गया है। ■

आतंकवाद न तो लेफ्ट होता है न ही राइट, केवल आतंकवाद होता है: अमित शाह

संसद ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल (संसोधन) 2019 को मंजूरी दे दी। केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने संसद के दोनों सदनों में विधेयक पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पोटा को भंग करना उचित नहीं था, इससे आतंकवाद इतना बढ़ा कि स्थिति काबू में नहीं रही।

लोकसभा

कें द्रीय गृह मंत्री व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल (संसोधन) 2019 पर चर्चा करते हुए 15 जुलाई को लोकसभा में कहा कि आतंकवाद ना तो लेफ्ट होता है ना राइट होता है, केवल आतंकवाद होता है। इसके खिलाफ लड़ने की सरकार, संसद, सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। अगर एन.आई.ए. बिल पर संसद बंट गई तो आतंकवादियों का मनोबल बढ़ेगा।

श्री शाह ने कहा आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने वाली किसी एजेंसी को और ताकत देने की बात हो और सदन एक मत न हो, इससे आतंकवाद फैलाने वालों का मनोबल बढ़ता है। मैं सभी दलों के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये कानून देश में आतंकवाद से निपटने में सुरक्षा एजेंसी को ताकत देगा।

श्री शाह ने कहा पोटा को भंग करना उचित नहीं था, ये पूर्व के सुरक्षा बलों के अधिकारियों का भी मानना है। इससे आतंकवाद इतना बढ़ा कि स्थिति काबू में नहीं रही और एनआईए को लाने का फैसला किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा हमें उन विधवाओं और उन परिवारों की भी चिंता है जो आतंकवाद के कारण प्रभावित होते हैं।

श्री शाह ने बताया कि एन.आई.ए. विशेष कोर्ट को डेजिनेट करने से उस कोर्ट के जज के स्थानांतरण आदि के कारण कोर्ट खाली नहीं रहेगी और समय पर केस का निपटारा हो पायेगा। एन.आई.ए. अदालत के जजों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही करते रहेंगे, जिस तरह अभी प्रक्रिया चल रही है। आतंकवाद के विषय पर केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी। दोनों में तालमेल रहेगा।

गृह मंत्री ने सदन को बताया कि एन.आई.ए. का रिकॉर्ड 90 परसेंट सफलता का है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट है। श्री अमित शाह ने कहा कि समझौता ब्लास्ट में कुछ लोगों को पकड़ा गया था, भारत के अलावा अमेरिकन एजेंसियों ने भी कहा कि इन लोगों ने समझौता ब्लास्ट किया, किंतु पकड़े गए लोगों को छोड़ा गया उसके बाद दूसरे लोगों को पकड़ा गया। यह पूछा जाना चाहिए था कि जिन्होंने ब्लास्ट किया था उनको क्यों छोड़ा गया और किसके कहने पर छोड़ा गया।

श्री शाह ने कहा कि जब आप किसी के साथ खिलाफ उंगली करते



हैं तो एक उंगली उसके खिलाफ होती है किंतु अपनी तरफ चार उंगलियां इशारा करती हैं।

राज्यसभा

राजनीतिक आधार पर एनआईए की कुशलता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिये: गृह मंत्री

केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल (संसोधन) 2019 पर चर्चा करते हुए 17 जुलाई को राज्यसभा में कहा कि दुनिया में जहां भी भारतीयों के खिलाफ आतंकवादी हमला होगा, एनआईए जांच कर सकेगी।

श्री अमित शाह ने कहा आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने वाली एजेंसी को और ताकत देने की बात हो तो सदन को एक मत होना चाहिये और इस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिये।

श्री शाह ने कहा कि राजनीतिक आधार पर एनआईए की कार्य कुशलता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। सदन को आश्वस्त करते हुए गृह मंत्री ने कहा नरेंद्र मोदी सरकार एनआईए का कभी दुरुपयोग नहीं करेगी।

गृह मंत्रालय के अनुसार 30.06.2019 तक एनआईए ने 272 केस रजिस्टर किए हैं। उनमें से 199 पर चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। 51 मामलों में फैसला सुनाया जा चुका है जिनमें 46 मामलों में अभियुक्तों को सजा हुई है। ■



मोदी सरकार 2.0 के प्रथम 50 दिन श्रम सुरक्षा से अनौपचारिक क्षेत्र के 40 करोड़

सार्वजनिक बैंकों में पूंजी बढ़ाने के लिए 70,000 करोड़ रुपये

भा जपानीत केंद्र की राजग सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के प्रथम 50 दिनों में ही कई महत्वपूर्ण कार्य किए। मोदी सरकार 2.0 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सबके लिए सुधार, कल्याण और न्याय का संकल्प सरकार के लिए प्रेरक शक्ति रहा है। केंद्रीय सरकार मुख्य रूप से किसानों, सैनिकों, युवाओं, श्रमिकों, व्यापारियों, अनुसंधान कार्यो, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर ध्यान देने के साथ-साथ निवेश, आधारभूत विकास, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और सामाजिक न्याय पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है।

दरअसल, केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने 22 जुलाई को सरकार के कई निर्णयों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सभी किसानों को अब 6,000 रुपये दिये जायेंगे। कई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को दोगुना किया गया है, जो कुछ मामलों में 2014 की दरों की तुलना में तिगुना भी हो गया है।

भारत 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। स्टार्टअप उद्योगों के लिए जल्द ही एक अलग टीवी चैनल शुरू किया जायेगा। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों के लिए गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया है। अगले पांच वर्षों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा।



100 करोड़ कामगारों को लाभ

के व्यापक समाधान के लिए अभियान के रूप में काम कर रही है, अलग से जल शक्ति मंत्रालय का गठन इसी महत्व को उजागर करता है।

श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों से जुड़ी घटनाओं में कमी लाने में सरकार को सफलता मिली है। प्रधानमंत्री के मालदीव और श्रीलंका के दौरे के महत्व के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिस्सेक और जी-20 के माध्यम से अपना देश एक वैश्विक नेतृत्व के रूप में उभरा है।

श्री जावडेकर ने चन्द्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण के प्रति आत्मविश्वास व्यक्त किया और बताया कि 2022 में गगनयान का प्रक्षेपण किया जायेगा, जो भारत का अंतरिक्ष के लिए एक मानव-

किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाये जा रहे हैं। श्रम कानून में परिवर्तन होने से मजदूरी और श्रम सुरक्षा द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र के 40 करोड़ कामगारों को लाभ मिलेगा। व्यापारियों को पहली बार पेंशन दिया जा रहा है। आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध सशक्त कार्रवाई के लिए कई कदम उठाये गये हैं।

उन्होंने कहा कि किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाये जा रहे हैं। श्रम कानून में परिवर्तन होने से मजदूरी और श्रम सुरक्षा द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र के 40 करोड़ कामगारों को लाभ मिलेगा। व्यापारियों को पहली बार पेंशन दिया जा रहा है। श्री जावडेकर ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं, दोनों के लिए ईएसआई अंशदान दरों में कटौती के बारे में भी चर्चा की।

श्री जावडेकर ने देश में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से उठाये गये कदमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक बैंकों में पूंजी बढ़ाने के लिए 70,000 करोड़ रुपये दिये गये हैं। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप उद्योगों के लिए जल्द ही एक अलग टीवी चैनल शुरू किया जायेगा। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों के लिए गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया है।

श्री जावडेकर ने कहा कि अगले पांच वर्षों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल से जुड़ी समस्याओं

सहित मिशन होगा।

श्री जावडेकर ने नौकरशाही में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी व्यापक कार्रवाई के बारे में भी बताया। आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध सशक्त कार्रवाई के लिए कई कदम उठाये गये हैं। फर्जी योजनाओं के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एक विधेयक पारित किया जा रहा है।

श्री जावडेकर ने पॉक्सो कानून में संशोधन के जरिये यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार की इच्छा-शक्ति के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने देश में चिकित्सा शिक्षा में सुधार के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा से जुड़े प्रशासन, उत्तरदायित्व और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में चर्चा की।

श्री जावडेकर ने जोर देकर बताया कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थ व्यवस्था बनाना महज एक कल्पना नहीं है, बल्कि इन 50 दिनों में इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक योजनाबद्ध खाका भी तैयार किया गया है। ■



पार्टी को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने के लिए मेहनत करें : जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने झारखंड में 13 एवं 14 जुलाई 2019 को दो दिवसीय प्रवास किया। 13 जुलाई को उन्होंने रांची में पार्टी के विभिन्न वर्ग के नेताओं के साथ अलग-अलग स्तर पर बैठक की।

श्री नड्डा ने प्रदेश भाजपा को राज्य में 25 लाख नए भाजपा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की और स्पष्ट कहा कि इस लक्ष्य को हर हाल में हासिल करना है। श्री नड्डा ने झारखंड के लिए बूथ स्तर पर तय किए गए लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने की बात कही।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह ने बैठक के बाबत मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने बूथ स्तर पर 23 तरह के दायित्व लोकसभा चुनाव से पूर्व सौंपे थे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने उन सभी का अनुपालन विधानसभा चुनाव में भी करने को कहा है। सदस्यता अभियान पर चर्चा करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश भाजपा ने 25 लाख नए सदस्य बनाने का जो लक्ष्य तय किया है, उसे हर हाल में हासिल करना है।

प्रदेश के शीर्ष नेता इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिलों में प्रवास करें। शीर्ष टीम से लेकर मंडल स्तर तक के पदाधिकारी विस्तारक के रूप में सात दिनों तक प्रवास करें। उन्होंने भाजपा के प्रत्येक पदाधिकारियों को पांच-पांच बूथों की जवाबदेही भी सौंपी। कहा, लोकसभा चुनाव में 14 में से 12 सीटें एनडीए गठबंधन ने हासिल की थीं, भाजपा का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा हुआ है, जबकि विपक्ष का मनोबल गिरा हुआ है।

इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सर्वश्री अरुण सिंह, मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा, भाजपा के सह प्रभारी राम विचार नेताम, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद जयंत सिन्हा, सुदर्शन भगत, राज्य सरकार के मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र राय, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, दीपक प्रकाश व अनंत ओझा उपस्थित थे।

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश कार्यालय में हुई पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष व जिला प्रभारियों की बैठक में कहा कि आप सभी को गर्व होना चाहिए कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं। एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं, जो लगातार सफलता हासिल कर रही है। जबकि, विपक्ष विशेषकर कांग्रेस का नेतृत्व भ्रमित है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि भाजपा विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता भी अपने दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अब सब भाजपा की विचारधारा को स्वीकारने लगे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, आदिवासी व अनुसूचित जाति हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी गरीबों के लिए केंद्र में और मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्य में लगातार काम कर रहे हैं।

उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि वे केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करें। प्रदेश सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि रघुवर सरकार ने हर पहलू पर सफलता हासिल की है। भाजपा कार्यकर्ताओं को इस पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा, पार्टी को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने के लिए मेहनत करें। सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएं। विश्वास जताया कि भाजपा झारखंड में

सदस्यता अभियान का पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी।

झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि विधानसभा चुनाव में 65 प्लस का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें एक करोड़ वोट प्राप्त करने होंगे। प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक में मुख्यमंत्री ने इस लक्ष्य के साथ ही सदस्यता अभियान पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, 25 लाख सदस्यता के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। राज्य की जनता को भाजपा से जुड़ने की उत्सुकता है।

बस हमें अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ घर-घर पहुंचने की आवश्यकता है। प्रदेश अध्यक्ष श्री लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि लोकसभा चुनावों में हमें अथक परिश्रम से बड़ी जीत मिली है। हमें इस उत्साह को जन-जन से जोड़ना है। सदस्यता अभियान के जरिए जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रदीप वर्मा ने किया।

राज्य सरकार किसानों और मजदूरों को सबल बना रही है

गत 14 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डु ने कहा कि सरकार वह जो जनता का दुःख दर्द समझे और उसे दूर करे। झारखंड एक ऐसा ही राज्य है। देश की आयुष्मान योजना सहित सभी योजनाओं को लागू करने में झारखंड पूरे देश में सबसे अक्ल राज्य में है। झारखंड सरकार गरीबी दूर करने के लिए किसानों और मजदूरों को सबल बना रही है। चौतरफा प्रयास से काम हुए हैं और राज्य की गरीबी कम हुई है।

श्री नड्डु रांची जिले के ओरमांडी प्रखंड स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय परिसर पांचा में पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कल्याण मंत्री झारखंड सरकार डॉ. लुईस मरांडी, शिक्षा मंत्री डॉ. नीरा यादव, रांची लोकसभा सांसद सर्वश्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद समीर उरांव, विधायक राम कुमार



पाहन, अनंत ओझा सहित अन्य गणमान्य लोग एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि पिछले साढ़े 4 वर्ष में सरकार के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ा है। देश के गांव, गरीब, किसान, महिला एवं नौजवान के जीवन में बदलाव लाने का कार्य सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से विकास कर रहा है। देश और झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली



लाना प्रधानमंत्री की सोच रही है। किसानों के चेहरे पर मुस्कराहट हो इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान योजना एवं राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लागू करने का कार्य किया है।

श्री दास ने कहा कि सितंबर 2019 से राज्य के 35 लाख किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ मिलना शुरू होगा। आने वाले 3 महीनों के भीतर सरकार द्वारा राज्य के 35 लाख किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से योजना की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड के किसानों को सरकार द्वारा 5 हजार करोड़ की राशि उनके विकास के लिए खर्च की करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान सरकार के गठन के बाद से ही महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर रहा है। वर्ष 2014 से अब तक राज्य में 1 लाख 90 हजार से भी अधिक सखी मंडलों का गठन किया गया। इन सखी मंडलों को रोजगार के विभिन्न आयामों से जोड़ने का भी प्रयास किया गया और रोजगार उपलब्ध कराए गए। मुख्यमंत्री दास ने कहा कि राज्य में गठित सखी मंडलों के आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस बड़ी राशि से इनके आर्थिक विकास को गति मिलेगी। अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आने वाले समय में आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट का सप्लाय सखी मंडल की बहनें ही करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सच है कि हमारा झारखंड बहुत ही समृद्ध राज्य है, परंतु यह एक सच्चाई भी है कि समृद्ध राज्य की गोद में गरीबी भी पल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार झारखंड में पल रही इस गरीबी को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध प्रयास कर रही है। ■



महाराष्ट्र

भाजपा के पास नेता भी हैं, नीति भी है और नीयत भी

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि देश बदल गया है और अच्छे दिन आ गए हैं। गत 21 जुलाई को मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र भाजपा की कार्यसमिति की बैठक में श्री नड्डा ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं देश बदल रहा है ये मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ। उन्होंने कहा कि देश बदल गया है ये हमें समझाने की जरूरत है।

भाजपा को नीति, नीयत और नेता वाली पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा, “राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कई पार्टियों के पास नेता हैं पर नीयत नहीं। कुछ के पास नीयत है तो नीति नहीं है। लेकिन भाजपा के पास नेता भी हैं, नीति भी है, नीयत भी है, वातावरण भी है और कार्यक्रम व कार्यकर्ता भी हैं।”

श्री नड्डा ने इस दौरान मोदी सरकार के उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 1971 से लेकर 2014 तक बैंकों में सिर्फ पौने 3 करोड़ बचत खाते खोले गए। जबकि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद जन धन योजना के माध्यम से 36 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। जिनमें एक लाख करोड़ से अधिक की धनराशि जमा की हुई है।

श्री नड्डा ने कार्यक्रम में भाजपा के सदस्यता अभियान की चर्चा

की। उन्होंने कहा कि अभी भाजपा के 11 करोड़ सदस्य हैं तथा पार्टी ने 10 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से कई पार्टियों के पास नेता हैं पर नीयत नहीं है। परंतु भाजपा के पास नेता भी है और नीयत भी।

भाजपा ने महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव में 220 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। राज्य कार्यसमिति की बैठक में यह फैसला हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया कि वह दोबारा सत्ता में लौटेंगे। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ भाजपा नहीं, बल्कि पूरी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री हैं।

इससे पूर्व 20 जुलाई को यहां भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश भाजपा नेताओं के साथ बैठकें कीं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र के दौरे पर आये श्री नड्डा ने पार्टी के सांसदों, विधायकों, जिला इकाई प्रमुखों, चुनाव तैयारी समिति और विस्तारित कोर टीम के साथ बैठकें कीं। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, श्री रावसाहेब दानवे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री चंद्रकांत पाटिल इन बैठकों में उपस्थित थे। ■

आर्थिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 1971 से लेकर 2014 तक बैंकों में सिर्फ पौने 3 करोड़ बचत खाते खोले गए। जबकि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद जन धन योजना के माध्यम से 36 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। जिनमें एक लाख करोड़ से अधिक की धनराशि जमा की हुई है।

‘आप और हम मिलकर अपना सर्वोच्च हासिल करेंगे’

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने गुजरात में 19 एवं 20 जुलाई को दोदिवसीय प्रवास किया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आज गुजरात की धरती पर आया हूँ, ये धरती दुनिया को संदेश देने वाली धरती है। ये बापू, सरदार पटेल, नरेंद्र मोदी की धरती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने अपना परचम लहराया है।

आगे बोलते हुए श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। 2014 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पार्टी ने अपनी संख्या आगे बढ़ाई। जनता ने चाहा था कि मोदी सरकार आए और एक बार फिर मोदी सरकार आई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह कहते हैं कि पार्टी को अभी अपना सर्वोच्च देना बाकी है। आप और हम मिलकर हम अपना सर्वोच्च हासिल करेंगे।

‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ बन चुका है आजाद भारत का तीर्थस्थल

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 20 जुलाई को कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है और यहां की यात्रा को आजाद ‘‘भारत के तीर्थाटन’’ के समान कहा जा सकता है। श्री नड्डा अपने दो दिन के दौरे के अंतिम दिन गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा बांध के समीप एक टापू पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति को देखने गए। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद भाजपा शासित गुजरात का यह उनका पहला दौरा है।



‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ की यात्रा के दौरान श्री नड्डा ने संवाददाताओं से कहा, ‘यह (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा) आजाद भारत का तीर्थस्थल बन चुका है। मुझे इसका सौभाग्य मिला। सरदार वल्लभभाई पटेल के आजाद भारत में योगदान के लिए मैं इसे भारत का तीर्थ मानता हूँ।’ उन्होंने कहा कि 565 छोटी-बड़ी रियासतों को एकजुट करने में पहले गृह मंत्री के रूप में पटेल की भूमिका के कारण भारत एक मजबूत देश बन सका।

उन्होंने कहा कि हम उनके बलिदान को नहीं भूल सकते। यह स्थान हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें मजबूत भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में काम करने के लिए प्रेरित करता है। श्री नड्डा के साथ राज्य के मंत्री सर्वश्री भूपेंद्रसिंह चूडासमा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जीतू वघानी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी थे। ■



राज्यसभा: कामकाज के लिहाज से उपयोगी सत्र

मूपेन्द्र यादव, राष्ट्रीय महामंत्री, भाजपा व संसद सदस्य, राज्यसभा

हाल ही में राज्यसभा में विपक्षी दल के नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने संसदीय स्थायी और प्रवर समितियों को समीक्षा के लिए भेजे बगैर जल्दबाजी में कई कानून पारित करवाए हैं। आश्चर्यजनक है कि विपक्ष को इसबात पर आपत्ति है कि संसद अधिक कानून लाकर अपने समय का समुचित उपयोग कर रही है और सदन का वर्तमान सत्र पिछले अन्य सत्रों के मुकाबले ज्यादा सार्थक और उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

कानून बनाना और पहले से बने कानूनों में जरूरत के अनुरूप संशोधन करना, संसद का प्रमुख काम है। अब यह समझ से परे है कि यदि संसद ठीक से ढंग अपने मूल कार्य को करते हुए कानून बना रही है अथवा संशोधन कर रही है तो इससे किसी दल को भला क्या समस्या हो सकती है?

राज्यसभा में विधेयकों को संसदीय समितियों को नहीं भेजने तथा उसकी जांच को लेकर विपक्षी दलों द्वारा जो आरोप लगाये जा रहे हैं, वह पूरी तरह से निराधार और तथ्यों से परे हैं। सही तथ्य यह है कि यूपीए सरकार ने वर्ष 2009 से 2014 तक राज्यसभा में केवल पांच विधेयकों को संसद की प्रवर समिति को भेजा था, जबकि एनडीए सरकार ने वर्ष 2014 से 2019 के बीच राज्यसभा में संसद की प्रवर समिति को कुल 17 विधेयक समीक्षा के लिए भेजे हैं। इससे

साफ़ होता है कि विधेयकों को संसद की समितियों के पास नहीं भेजने को लेकर विपक्ष का आरोप पूरी तरह से तथ्यहीन है।

आज जो लोग राज्यसभा सत्र के दौरान संसदीय गतिविधियों के दौरान चर्चाओं और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को बाधित कर रहे हैं, वही लोग आज सदन में सुचारू ढंग से हो रहे कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। संसद के कामकाज के बारे में निराधार टिप्पणी करने वालों को स्वयं से यह सवाल करना चाहिए कि आखिर मानसून सत्र 2015, बजट सत्र 2018,

और प्रावधान को प्रवर समिति नहीं भेजा जाता था। यह ठीक है कि प्रवर समितियों को विधेयक भेजना सदन की प्रक्रिया का हिस्सा रहा है, किन्तु यह भी सच है कि ऐसा विधेयक के लिए अनिवार्य नहीं है। कभी-कभी प्रवर समितियां कानून में फेरबदल करने की सलाह देती रही हैं और इसके परिणामस्वरूप कुछ विधेयकों में उन सिफारिशों को लागू भी किया जाता रहा है।

यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसकी अनदेखी हम नहीं कर सकते हैं, कुछ विधेयकों पर प्रवर समितियों में विचार होने के बावजूद सदन का सत्र नहीं होने की वजह से पारित नहीं हो पाते हैं। इस कारण उन विधेयकों को दोबारा सदन पटल पर रखना पड़ता है या सदन में लाया जाता है। इस तरह के विधेयकों में ज्यादातर वे हैं जो लोकसभा द्वारा पारित भी हुए तथा स्थायी समिति द्वारा उन्हें अनुमोदित भी किया गया था, लेकिन उन विधेयकों को लैप्स होने के

विपक्षी दलों द्वारा जो आरोप लगाये जा रहे हैं, वह पूरी तरह से निराधार और तथ्यों से परे हैं। सही तथ्य यह है कि यूपीए सरकार ने वर्ष 2009 से 2014 तक राज्यसभा में केवल पांच विधेयकों को संसद की प्रवर समिति को भेजा था, जबकि एनडीए सरकार ने वर्ष 2014 से 2019 के बीच राज्यसभा में संसद की प्रवर समिति को कुल 17 विधेयक समीक्षा के लिए भेजे हैं।

शीतकालीन सत्र 2018 और अंतरिम बजट सत्र 2019 में कामकाज की गति क्यों ठप जैसी हो गयी थी? हैरानी की बात है कि सदन में सकारात्मक रुख के साथ बहस और चर्चा करने की बजाय अनेक अवसरों पर गतिरोध पैदा करने वाले आज इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि सदन का प्रदर्शन अच्छा क्यों हो रहा है!

यह संसदीय परंपरा का ही हिस्सा रहा है कि केंद्र सरकार के किसी भी संस्थान को सशक्त करने से जुड़े आमूलचूल संशोधन

कारण सदन में वापस लाना पड़ा। उदाहरण के लिए द मोटर व्हीकल्स (अमेंडमेंट) बिल 2019, जिसकी समीक्षा पहले स्टैंडिंग कमेटी द्वारा की गयी, फिर लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद राज्यसभा ने इस बिल को प्रवर समिति के पास भेज दिया था, लेकिन लैप्स होने के कारण इसे फिर से लोकसभा में लाना पड़ा। इसी तरह ट्रिपल तलाक बिल में विपक्ष के सुझाव पर संशोधन करके दो बार इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया है। चूंकि इसे राज्यसभा

में यह दो बार पारित नहीं हो सका अंतः इसे फिर तीसरी लोकसभा में पारित कराना पड़ा है।

ऐसे अनेक विधेयक हैं जिन पर या तो प्रवर समिति या स्थायी समिति में विचार हो चुका है और इन्हें राज्यसभा द्वारा अभी पारित होना है: मसलन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019, सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2019, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019, वेतन संहिता 2019, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2019 तथा कंपनी संशोधन विधेयक 2019.

पिछले संसदीय सत्रों की तुलना में वर्तमान सत्र कानून के अधिनियमन के लिहाज से अधिक प्रभावी रहा है। यह सत्र संसद के सामान्य समय अवधि के मुकाबले अधिक कामकाज के लिहाज से अधिक उपयोगी भी रहा है और कई बार सदन की कार्यवाही सायंकाल 6 बजे से अधिक भी चली है। इस सत्र में विधेयकों के पारित होने के अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा भी हुई है, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सार्वजनिक महत्व के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सदन में चर्चा हुई है। इन सबके अतिरिक्त इसबार के सत्र के

कामकाज में कई मुद्दों से जुड़े निजी प्रस्ताव और सदस्यों के निजी बिल भी शामिल हैं। इस सत्र में प्रश्नकाल भी सार्थक रहा है जो कि सरकार की जवाबदेही के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौर करने वाला महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि हाल के पांच सत्रों में से चार सत्र बर्बाद चले गए, इसके बावजूद एनडीए सरकार के दौरान 2014 से 2019 के मध्य कम समय के

उसके आवंटित समय के अनुसार उपरोक्त समिति द्वारा पारित होने के बाद सूचीबद्ध किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि लंबे समय के बाद लांग ऑवर चर्चाएँ सदन में फिर से होने लगी हैं। ऐसा तब हुआ है जब व्यवधानों और अनावश्यक हस्तक्षेपों के कारण संसदीय सत्र अनियमित रहे हैं।

कानून बनाना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और विपक्ष की रचनात्मक प्रतिक्रिया और सार्थक हस्तक्षेप इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन केवल विरोध के लिए विपक्ष को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। विपक्ष को यह समझने की आवश्यकता है कि किसी भी विधेयक के संबंध में सहमति-असहमति की प्रतिक्रिया स्वीकार्य है, परंतु अनावश्यक बाधा उत्पन्न करना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। विपक्ष को अपनी भूमिका के महत्व का एहसास करने और रचनात्मक विपक्ष के रूप में कार्य करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में समझदारी से काम करने की आवश्यकता है। संसदीय कामकाज के लिहाज से यह उत्साहजनक है कि इस सत्र के दौरान सदन का कामकाज पहले की किसी भी अन्य सरकारों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से पूरा हो रहा है। ■

विपक्ष को यह समझने की आवश्यकता है कि किसी भी विधेयक के संबंध में सहमति-असहमति की प्रतिक्रिया स्वीकार्य है, परंतु अनावश्यक बाधा उत्पन्न करना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। विपक्ष को अपनी भूमिका के महत्व का एहसास करने और रचनात्मक विपक्ष के रूप में कार्य करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में समझदारी से काम करने की आवश्यकता है।

लिए अवधि की जो चर्चाएं हुईं उनकी कुल संख्या 29 थी। यह वर्ष 2009 से 2014 के दौरान यूपीए सरकार की 27 चर्चाओं से अधिक है।

संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा सदन के कामकाज को अंतिम रूप दिया जाता है, जिसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है और सभी विधेयकों को



कमल संदेश अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

पड़ोसी देशों से संबंध सुधार के प्रयास

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा के लिए मालदीव और श्री लंका का चयन किया। यह उनकी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रखने की नीति का ही हिस्सा था। पाकिस्तान इसका अपवाद है। मोदी ने कहा भी है कि पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा करेगा, तभी उसके साथ वार्ता हो सकती है। नरेन्द्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण में बिम्सटेक देशों को बुलाया था। आठ देशों के नेता शपथ ग्रहण में शामिल हुए। इन सभी के साथ नरेन्द्र मोदी ने द्विपक्षीय व क्षेत्रीय विषयों पर वार्ता की। इसमें आपसी संबन्ध सुधारने के साथ साथ बिम्सटेक देशों के बीच सहयोग बनाने पर सहमति बनी।

शपथ ग्रहण के फौरन बाद मोदी ने बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के शासकों से वार्ता की थी। भारत इन देशों में कई योजनाएं चला रहा है। मोदी ने इसकी भी समीक्षा की। उन्होंने यह भी कहा कि बिम्सटेक के बीच सहयोग बढ़ाने की व्यापक संभावना है। इस संगठन में पाकिस्तान शामिल नहीं है। ऐसे में आपसी संबंधों के बीच आतंकवाद की बाधा नहीं है। पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों की वजह से ही सार्क निष्फल हुआ था। इसीलिए नरेन्द्र मोदी ने उसमें समय लगाना व्यर्थ समझ लिया था। इसके बाद उन्होंने बिम्सटेक के साथ सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया था। मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरींग से वार्ता की थी। इसके

अलावा किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाय जेनेबकोव से भी मुलाकात हुई। इस समय किर्गिस्तान शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) का अध्यक्ष है। मध्य एशिया में भारत का प्रमुख सहयोगी है। राष्ट्रपति ने जेनेबकोव एससीओ सम्मेलन में शामिल होने के लिए मोदी को आमंत्रित किया है। 1997 में बैंकाक में बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों ने बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाइलैंड इकनॉमिक कोऑपरेशन अर्थात बीसटेक का गठन किया था। कुछ महीने बाद म्यांमार भी इसमें शामिल हो गया। 2004 में नेपाल और

पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा करेगा, तभी उसके साथ वार्ता हो सकती है। नरेन्द्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण में बिम्सटेक देशों को बुलाया था। आठ देशों के नेता शपथ ग्रहण में शामिल हुए। इन सभी के साथ नरेन्द्र मोदी ने द्विपक्षीय व क्षेत्रीय विषयों पर वार्ता की। इसमें आपसी संबन्ध सुधारने के साथ साथ बिम्सटेक देशों के बीच सहयोग बनाने पर सहमति बनी।

भूटान इसके पूर्ण सदस्य बन गए। इसके बाद इसका नाम बिम्सटेक हो गया।

मालदीव बिम्सटेक का सदस्य नहीं है। यही कारण है कि नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण में उसको आमंत्रित नहीं किया गया था। मोदी ने स्वयं मालदीव जाकर दोस्ती का पैगाम दिया है। यहां भी नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद की समस्या को प्रमुखता से उठाया। उनका स्पष्ट मानना है कि आतंकवाद आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने और मुक्त व्यापार की राह में सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए इसके मुकाबले की साझा रणनीति बनानी होगी। मालदीव चीन की कुटिल हस्तक्षेप नीति को भी समझ चुका है। वह भारत से सहयोग बढ़ाने को उत्सुक है। इसलिए भी

मोदी ने मालदीव जाने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को धन और हथियारों की आपूर्ति एक देश से ही होती है। मोदी का स्पष्ट इशारा पाकिस्तान की तरफ था।

ऐसे मुल्क पर अन्तरराष्ट्रीय दबाव होना चाहिए। आतंकवाद का प्रत्येक रूप खराब होता है। इसी से विश्व को निपटना है। नरेन्द्र मोदी के भाषण को मालदीव की संसद में गर्मजोशी के साथ सुना गया। उन्होंने कहा कि मालदीव में आजादी, लोकतंत्र, खुशहाली और शांति के समर्थन में भारत उसका सहयोगी रहेगा। मालदीव के साथ कई प्रमुख बातों पर सहमति भी कायम हुई है। वहां के राष्ट्रपति के साथ मोदी की वार्ता उपयोगी रही। दोनों देशों के बीच जल परिवहन पर भी सहमति बनी है।

पर्यावरण के बिगड़ने का प्रतिकूल प्रभाव मालदीव पर पड़ रहा है। नरेन्द्र मोदी ने इस पर चिंता व्यक्त की। कहा कि भारत उसके संकट को दूर करने में पूरा सहयोग करेगा। देशों के

बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। मोदी ने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र हमारी जीवन रेखा है। यह व्यापार का हाईवे भी है। इसमें खुलापन और संतुलन स्थापित करने के प्रयास किये जाएंगे। नरेन्द्र मोदी को मालदीव ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इज्जुद्दीन से विभूषित किया। इसे उन्होंने केवल अपने ही नहीं पूरे भारत का गौरव बताया।

वह राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के निमंत्रण पर मालदीव गए थे। यह यात्रा भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान में नई गति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंधों में हाल के

समय में हुई प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। नरेन्द्र मोदी की मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से सहयोग के अनेक विषयों पर वार्ता हुई। यह यात्रा भारत और मालदीव के रिश्तों को मजबूत बनाने वाली साबित हुई। इस यात्रा से दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में हुई प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिला।

इसी प्रकार नरेन्द्र मोदी की श्रीलंका यात्रा भी बहुत उपयोगी रही। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के साथ वार्ता में अनेक विषयों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। मालदीव और श्रीलंका की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पड़ोस प्रथम नीति और सागर सिद्धांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। सागर सिद्धांत का मतलब क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास है। यह सागर के माध्यम से आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के भारत की भारतीय रणनीति का हिस्सा है।

कोलंबो में नरेन्द्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने विश्व में भारत की छवि बदलने का श्रेय दुनिया के अलग-अलग कोने में रहने वाले भारतीयों

मोदी की विदेश यात्रा में औपचारिक समझौते भी हुए। भारत और मालदीव के बीच एमओयू का आदान प्रदान किया गया। जलमार्ग क्षेत्र में सहयोग, स्वास्थ्य सेवा, समुद्र द्वारा यात्री कार्गो सेवा की स्थापना के लिए दोनों देशों के बीच एमओयू हुआ। इसके साथ ही मालदीव में सिविल सेवक के लिए सीमा शुल्क क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग और व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता किया गया।

को दिया। अब भारत को देखने का दुनिया का नजरिया बदला है। भारत में लोकतंत्र लोगों के संस्कारों में है। भारत का गौरव बढ़ाने में विश्व में फैले हुए भारतीयों ने बड़ी भूमिका निभाई है।

मोदी की विदेश यात्रा में औपचारिक समझौते भी हुए। भारत और मालदीव के बीच एमओयू का आदान प्रदान किया गया। जलमार्ग क्षेत्र में सहयोग, स्वास्थ्य सेवा, समुद्र द्वारा यात्री कार्गो सेवा की स्थापना के लिए दोनों देशों के बीच एमओयू हुआ। इसके साथ ही मालदीव में सिविल सेवक के लिए सीमा शुल्क क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग और व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता किया गया। मोदी मालदीव में रूपे कार्ड जारी करने से मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी। भारत इस दिशा में प्रयास करेगा। इसके अलावा रक्षा सेवाओं को मजबूत बनाने और कोच्चि से मालदीव तक नौकासेवा शुरू करने पर भी सहमति बनी। जाहिर है कि मोदी की विदेश यात्रा में कई उपलब्धि शामिल हुई है। ■

(हि.स.) (लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

लोकसभा की उत्पादकता 20 साल में सबसे ज्यादा

भा जपानीत केंद्र की राजग सरकार के भरपूर प्रयासों के कारण 17वीं लोकसभा 20 साल में सबसे ज्यादा उत्पादक रही। ज्यादा से ज्यादा काम हों, इसलिए बैठक की अवधि बढ़ाई जा रही है जिसके कारण उत्पादकता बढ़ रही है।

पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार 16 जुलाई तक लोकसभा की उत्पादकता 128% रही जो 20 वर्षों के दौरान आहत किसी भी सत्र के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसने करीब-करीब 125% उत्पादकता वाले 2016 के बजट सत्र और फिर 2014 के शीत सत्र को पीछे छोड़ दिया।

सबसे ज्यादा उत्पादक दिन 11 जुलाई रहा जब सदन में रेल मंत्रालय के लिए लेखा अनुदान पर मध्य रात्रि तक बहस हुई। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला ने लोकसभा सचिवालय को सुबह तक के लिए जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था, क्योंकि पहले सुबह 3 बजे तक सदन चलाने की योजना बनी थी। 16 जुलाई को भी लोकसभा की कार्यवाही मध्य रात्रि तक चली।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सदन की बिना रुकावट चली कार्यवाही



पर कहा कि जरूरत हो तो सत्र को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, ताकि सारे काम निश्चित रूप से निपटा लिए जाएं। असल में सरकार नहीं चाहती कि कुछ अहम विधेयक लटके रहें। अब तक 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में आठ विधेयक पास हो चुके हैं। इस सत्र की खास बात ये भी है कि ज्यादातर नए सांसदों को बोलने का मौका मिला। ■

मंत्रिमंडल ने 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने की मंजूरी दी

प्र धानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति (सीसीईए) ने 24 जुलाई को निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी :

- ▶ 1 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक (एक वर्ष के लिए) 40 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चीनी का सुरक्षित भंडार बनाना और इसके लिए अधिकतम 1674 करोड़ रुपये अनुमानित खर्च करना। लेकिन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा बाजार मूल्य और चीनी की उपलब्धता के आधार पर किसी भी समय वापसी/संशोधन के लिए इसकी समीक्षा की जा सकती है।
 - ▶ योजना के अंतर्गत चीनी मिलों को तिमाही आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी जिसे चीनी मिलों की ओर से बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए सीधे किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा और यदि कोई बाधा का शेष होता है, तो उसे मील के खाते में जमा किया जाएगा।
- इससे निम्नलिखित लाभ होंगे :
- ▶ चीनी मिलों की तरलता में सुधार होगा।
 - ▶ चीनी इंडेन्ट्री में कमी आएगी।
 - ▶ घरेलू चीनी बाजार में मूल्य भावना बढ़ाकर चीनी की कीमतें स्थिर की जा सकेंगी और परिणामस्वरूप किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान समय से किया जा सकेगा।
 - ▶ चीनी मिलों के गन्ना मूल्य बकायों की मंजूरी से सभी गन्ना उत्पादक राज्यों में चीनी मिलों को लाभ होगा।

चीनी उत्पादन मौसम 2017-2018 में घोषित सुरक्षित भंडार सब्सिडी योजना 30 जून, 2019 को समाप्त हो गई है, लेकिन आगामी चीनी उत्पादन मौसम 2019-20 बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने/प्रारंभिक स्टॉक के साथ शुरू हो सकता है। इसलिए मांग आपूर्ति संतुलन बनाए रखने तथा चीनी की कीमतें स्थिर रखने के लिए सरकार ने 1 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने का फैसला किया है।



पृष्ठभूमि :

चीनी मौसम 2017-18 (अक्टूबर-सितंबर) तथा चीनी मौसम 2018-19 के दौरान चीनी के उत्पादन को देखते हुए और उद्योग में अधिक लाभ की स्थिति तथा तरलता में कमी को देखते हुए सरकार द्वारा समय-समय पर कदम उठाए गए हैं, ताकि चीनी मिलों की तरलता में सुधार हो सके और मीलें किसानों के बकाया गन्ना मूल्यों का भुगतान कर सकें तथा घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें स्थिर हो सकें।

सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए यानी 1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019 के लिए 30 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाना सरकार के विभिन्न कदमों में एक है। इसी के अनुसार सुरक्षित भंडार बनाने और रखरखाव के लिए योजना 15 जून, 2019 को अधिसूचित की गई।

चीनी उत्पादन मौसम 2017-2018 में घोषित सुरक्षित भंडार सब्सिडी योजना 30 जून, 2019 को समाप्त हो गई है, लेकिन आगामी चीनी उत्पादन मौसम 2019-20 बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने/ प्रारंभिक स्टॉक के साथ शुरू हो सकता है। इसलिए मांग आपूर्ति संतुलन बनाए रखने तथा चीनी की कीमतें स्थिर रखने के लिए सरकार ने 1 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने का फैसला किया है।

इसके लिए सरकार योजना में भाग लेने वाली चीनी मिलों को लगभग 1674 करोड़ रुपये की रखाव लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। इससे चीनी मिलों की तरलता स्थिति में सुधार होगा। योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रतिपूर्ति किसानों के बकाया गन्ना मूल्यों के भुगतान के लिए उनके खातों में चीनी मिलों द्वारा सीधा जमा किया जाएगा। ■

संसद ने आरटीआई संशोधन विधेयक को दी मंजूरी

संसद ने 25 जुलाई को सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन संबंधी एक विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार ने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पारदर्शिता, जन भागीदारी और सरलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्यसभा

विधेयक ध्वनिमत से पारित

राज्यसभा ने सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। साथ ही सदन ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिए लाये गये विपक्ष के सदस्यों के प्रस्तावों को 75 के मुकाबले 117 मतों से खारिज कर दिया।

इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे।

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्य मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि आरटीआई कानून बनाने का श्रेय भले ही कांग्रेस अपनी सरकार को दे रही है किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के शासन काल में सूचना के अधिकार की अवधारणा सामने आयी थी। उन्होंने कहा कि कोई कानून और उसके पीछे की अवधारणा एक सतत प्रक्रिया है जिससे सरकारें समय समय पर जरूरत के अनुरूप संशोधित करती रहती हैं।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के शासनकाल में एक ऐप जारी किया गया है। इसकी मदद से कोई रात बारह बजे के बाद भी सूचना के अधिकार के लिए आवेदन कर सकता है। श्री सिंह ने कहा कि आरटीआई



अधिनियम में पहले ही केंद्र को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, आज भी वही व्यवस्था है।

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि आरटीआई अधिनियम की धारा-13 में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तों का उपबंध किया गया है। इसमें कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन, भत्ते और शर्तें क्रमशः मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के समान होंगी।

इसमें यह भी उपबंध किया गया है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन क्रमशः निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव के समान होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के वेतन एवं भत्ते एवं सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य हैं।

वहीं, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के उपबंधों के अधीन स्थापित कानूनी निकाय है। ऐसे में इनकी सेवा शर्तों को सुव्यवस्थित करने की जरूरत है।

लोकसभा

सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध

लोकसभा ने 22 जुलाई को सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित कर दिया।

इस विधेयक की बहस में भाग लेते हुए केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस सिद्धांत का अनुपालन करते हुए सरकार ने आरटीआई की संख्या कम करने के लिए सरकारी विभागों को अधिकतम जानकारी देने के विस्तार को सरकार ने स्वतः प्रोत्साहित किया है।

इसके अलावा सरकार नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से शिकायतों के निवारण पर ध्यान दे रही है। इसने आरटीआई के प्रमुख सिद्धांत को मजबूत किया है और पिछले पांच वर्षों के दौरान आरटीआई आवेदनों के लंबित मामले काफी कम हुए हैं।

सदस्यों को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राज्य सूचना आयोगों के संबंध में नियमों को लागू करने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि 2005 के मूल आरटीआई अधिनियम के अनुसार सूचना आयुक्तों के संबंध में नियम लागू करने का अधिकार न तो केंद्र न राज्य और न ही समवर्ती सूची के दायरे में आता है, इसलिए राज्य सूचना आयोगों के संबंध में भी कानून बनाना केंद्र सरकार के शेष अधिकारों के अंतर्गत आता है। ■



कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और
दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र



नाम :

पूरा पता :

..... पिन :

दूरभाष : मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल :

सदस्यता	एक वर्ष	₹350/-	<input type="checkbox"/>	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	<input type="checkbox"/>
	तीन वर्ष	₹1000/-	<input type="checkbox"/>	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	<input type="checkbox"/>

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक :

नोट : डीडी / चेक 'कमल संदेश' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)



अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकजी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका



नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय से चंद्रयान-2 ले जाने वाले रॉकेट जीएसएलवी-मार्क III के सफल प्रक्षेपण को देखते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी



लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

